● वर्ष-5
● अंक-247
रायपुर, मंगलवार
02 जून 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› उद्योग मंत्री देवांगन ने किया...

परिसीमन विधेयक को फिर से लाने की तैयारी में मोदी सरकार

वन नेशन-वन इलेक्शन बिल का भी लक्ष्य

नई दिल्ली। परिसीमन विधेयक को संसद में पारित कराने के प्रयास में मिली करारी हार के बाद, सरकार एक बार फिर से इस विधेयक को लाने और साथ ही 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पश्चिम बंगाल में मिली जीत से उत्साहित भाजपा, संसद में एक-बार फिर से जोड़-तोड़ में लग गई है। यह सब तब हो रहा है जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करना चाहिए।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय एक नया परिसीमन विधेयक तैयार कर रहा है। यह नया प्रयास अप्रैल-मई में हुए विधानसभा चुनावों के बाद आया है, जिसने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में

टीएमसी और डीएमके को करारा झटका दिया और विपक्षी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया।

जोड़-तोड़ की राजनीति में लगी भाजपा

यह नया प्रयास अप्रैल-मई में हुए विधानसभा चुनावों के बाद आया है, जिसने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में टीएमसी और डीएमके को करारा झटका दिया और विपक्षी समीकरणों को बाधित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, डीएमके की करारी हार और कांग्रेस के टीवीके सरकार में शामिल होने के बाद, पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो भाजपा के साथकुछ खास मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हैं।

वहीं दूसरी ओर, भाजपा पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर बढ़ते मतभेदों और उसके नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते गुस्से पर पैनी नजर रख रही है। संसद में इन मुद्दों का क्या और कब असर होगा, यह भी भाजपा की आगे की रणनीति का एक अहम पहलू है।

वन नेशन-वन इलेक्शन की भी तैयारी तेज

इसके समानांतर, लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से लाए गए एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को औपचारिक रूप देने का काम चल रहा है। वर्तमान में, इसकी समीक्षा 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति कर रही है। एक नेता के मुताबिक विधेयक में जल्द ही संशोधन किया जाएगा। रिपोर्ट के संबंध में हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं और हम समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। जेपीसी का कार्यकाल मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया गया है।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में राज्यसभा उपचुनाव भी

27 राज्यसभा सीटों और विधान परिषद चुनावों की अधिसूचना जारी

- 18 जून को होगा मतदान, उसी दिन शाम को मतगणना
- नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने 27 राज्यसभा सीटों तथा तीन राज्यों की विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी सीटों के लिए मतदान 18 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू की जाएगी।

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 8 जून तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी, जबकि उम्मीदवार 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। तय कार्यक्रम अनुसार मतदान 18 जून सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और इसी दिन शाम बजे से मतगणना की जाएगी। आयोग के अनुसार, 10

चुनाव आयोग का पूरा शेड्यूल

♦नामांकन दाखिल करना शुरू - 1 जून, सुबह 11 बजे से।
♦नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख - 8 जून, दोपहर 3 बजे।
♦नामांकनों की जांच - 9 जून।
♦नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख - 11 जून।
♦वोटिंग का दिन - 18 जून, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक।
♦वोटों की गिनती - 18 जून, शाम 5 बजे से।

राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। वहीं, बिहार में विधान परिषद की नौ सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक में चार राज्यसभा और सात विधान परिषद सीटों पर भी मतदान होगा।

कर्नाटक में राज्यसभा की जिन चार सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें भाजपा के इराना कडाड़ी और नारायण कोरगाप्पा, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे तथा जद(एस) के एचडी देवगोड़ा का कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो रहा है। इसी तरह कर्नाटक विधान परिषद के सात सदस्यों का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है, जिसके चलते इन सीटों पर भी चुनाव कराए जा रहे हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज कोंडागांव जिले के ग्राम बड़ेकनेरा में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली।

फ्रांस से 114 लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। भारत ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सौदा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये का माना जा रहा है और इसे देश के सबसे बड़े रक्षा खरीद कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने पिछले सप्ताह फ्रांसीसी सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (एलओआर) भेजा है। इसके साथ ही सरकार-से-सरकार (जी2जी) आधार पर होने वाली इस रक्षा डील की औपचारिक शुरुआत हो गई है।बताया जा रहा है कि फ्रांस की ओर से अगले दो से तीन महीनों में जवाब मिलने की उम्मीद है, जबकि बातचीत पूरी कर एक

वर्ष के भीतर समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

यह खरीद वायुसेना के एमआरएफए कार्यक्रम का हिस्सा

यह खरीद भारतीय वायुसेना के मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट) कार्यक्रम का हिस्सा है। वायुसेना लंबे समय से अपने घटते फाइटर स्क्वाड्रन की समस्या से जूझ रही है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास करीब 29 स्क्वाड्रन हैं, जबकि स्वीकृत आवश्यकता 42.5 स्क्वाड्रन की है।

भारत के पास अभी 36 राफेल विमान

भारत पहले ही 2016 के भारत-फ्रांस समझौते के तहत 36 राफेल विमानों को शामिल कर चुका है। अब प्रस्तावित नई डील के तहत अधिकांश विमान भारत में ही तैयार किए जाएंगे। फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन और एक भारतीय साझेदार कंपनी के बीच सहयोग से लगभग 90 से 94 विमान देश में निर्मित किए जाने की योजना है, जबकि बाकी विमान सीधे फ्रांस से आएंगे।

रक्षा अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना में लगभग 50 प्रतिशत स्थानीयकरण (लोकलाइजेशन) हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यह राफेल कार्यक्रम के लिए भी एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि पहली बार इन विमानों का निर्माण फ्रांस के बाहर किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते से भारत को राफेल विमानों में स्वदेशी हथियार और प्रणालियां जोड़ने की सुविधा मिलेगी। साथ ही पूरी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त रखने पर जोर दिया गया है।

प्रमुख समाचार

बंगाल मंत्रिमंडल का विस्तार, 35 नए मंत्री बने, ली शपथ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सियासत में सोमवार को एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी कैबिनेट का पहला और सबसे बड़ा विस्तार कर दिया है। कोलकाता के राजभवन (लोक भवन) में

आयोजित एक भव्य और हाई-प्रोफाइल शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के 35 विधायकों ने मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आर. एन. रवि ने सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के साथ ही सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के गढ़ों को ध्वस्त करने वाले अपने सबसे भरोसेमंद और आक्रामक चेहरों को सरकार की कमान सौंप दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1 ए) के तहत किसी भी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित वहां की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस नियम के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 44 मंत्री हो सकते हैं।

बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन शुरू

पटना। बिहार में 10 सीटों पर बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन शुरु हो गया है। इस बीच सियासी हलचल भी तेज हो गई है। पटना में जेडीयू नेताओं के बीच मुलाकात हो रही। सोमवार को नीतीश कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और डिप्टी सीएम विजय चौधरी से उनके आवास पर जाकर

मुलाकात की। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह मुलाकात खास मानी जा रही है। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी शेड्यूल की माने तो, एक जून से आठ जून तक नामांकन होगा। नौ जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 11 जून तक नाम वापसी का समय है। दस नामांकन होने की स्थिति में 11 जून को नाम वापसी की समय खत्म हो जाने के बाद निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद दस से अधिक नामांकन की स्थिति में 18 जून को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा कोटे की इन दस सीटों के लिए 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाला जाएगा। शाम चार बजे के बाद मतों की गिनती होगी।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिले असम के सीएम हिमंत

नईदिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को यहां उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की। शर्मा ने 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ ली थी जिसके बाद उपराष्ट्रपति के साथ यह उनकी पहली मुलाकात है। राधाकृष्णन ने सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति

पद का कार्यभार संभाला था। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की।'' शर्मा ने इससे पहले दिसंबर 2025 में उपराष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उन्हें असम आने का न्योता दिया था। राधाकृष्णन ने इस साल मार्च में नगालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा का तीन दिवसीय दौरा किया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी सोमवार को उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत संधू को मार्च में दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था।

कर्नाटक सीएम पद के बाद अब दिल्ली में कैबिनेट पर महामंथन

नईदिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस हाई कमांड के साथ नए मंत्रिमंडल के गठन, विभागों के आवंटन और राज्य में महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियों पर अहम चर्चा के लिए मौजूद हैं। यह बैठक कर्नाटक कांग्रेस के भीतर मंत्री पदों के लिए

चल रही ज़ोरदार पैरवी और सामाजिक एवं क्षेत्रीय संतुलन के प्रयास के तहत एक या एक से अधिक उपमुख्यमंत्रियों की संभावित नियुक्ति की अटकलों के बीच हो रही है। शिवकुमार और सिद्धारमैया पार्टी नेतृत्व से परामर्श करने के लिए बेंगलुरु से दिल्ली तक एक साथ गए। सिद्धारमैया के बेटे और एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया के भी इन चर्चाओं में शामिल होने की उम्मीद है, जिससे नई सरकार में उनकी संभावित भूमिका को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस विधानसभा ने हाल ही में शिवकुमार को अपना नेता चुना है। जिससे उनके अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं।

भारत में अगले साल तक शुरू हो सकती है बुलेट ट्रेन सेवा

नई दिल्ली। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक बुलेट ट्रेन सेवा शुरू हो सकती है। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा बेहद कम समय में पूरी की जा सकेगी। लोग इस आधुनिक ट्रेन सेवा का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी। इससे व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि दुनिया में कई देश पहले से ही हाई-स्पीड रेल नेटवर्क में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन जापान की एल-0 सीरीज मैग्लेव मानी जाती है। इस ट्रेन ने ट्रायल के दौरान 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जापान की प्रसिद्ध शिंकान्सेन बुलेट ट्रेनें भी नियमित रूप से लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। खास बात यह है कि दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन सेवा भी जापान ने करीब छह दशक पहले शुरू की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में हाई-स्पीड रेल तकनीक का विस्तार हुआ।

चुनावी वादे पूरे करना नवनिर्वाचित सरकारों के लिए सिरदर्द

एम गोविंद राव

चार राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब नवनिर्वाचित सरकारों का ध्यान शासन प्रशासन पर रहेगा। अपने चुनाव घोषणापत्रों में उन्होंने भारी भरकम उपहारों का वादा किया था लेकिन खजाने में इसके लिए बहुत कम गुंजाइश है। इसलिए अब उन्हें बड़ी चिंता इस बात की होगी कि उन वादों को अमली जामा कैसे पहनाया जाए।

इन योजनाओं को लागू करना बड़ी चुनौती होगी क्योंकि ये राज्य पहले से ही वित्तीय दबाव में हैं। साथ ही पश्चिम एशिया में जंग के हालात भी राजस्व पर अच्छा खासा प्रतिकूल प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव डाल सकते हैं। इससे ऊर्जा और अन्य कच्चे माल की कीमतों पर भी असर होगा। जो वादे किए गए हैं उनकी कीमत अब बहुत अधिक होने वाली है क्योंकि ये वृद्धि को बढ़ावा देने वाले और मानव को सशक्त बनाने वाले दीर्घकालिक खर्च की जगह ले सकते हैं।

जिन चार राज्यों में चुनाव हुए उनमें से तीन में सत्ता परिवर्तन हुआ और केवल असम में ही पिछली सरकार बरकरार रही। चारों राज्यों में एक जैसी बात यह रही कि जीतने वाले राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए खूब बढ़ चढ़कर वादे किए। अब जब वे इन वादों को पूरा करने चलेंगे तब उनको अहसास होगा कि हालात कैसे हैं? विडंबना है कि चार में से तीन राज्य ङ्क केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल काफी समय से राजकोषीय दिक्कतों से जूझ रहे हैं और इस मुश्किल आर्थिक परिस्थिति में मुफ्त की रेवड़ियों के लिए संसाधन जुटाने का कोई आसान रास्ता उनके पास नहीं है। असम और पश्चिम बंगाल में जिस दल की सरकार बनी है वह केंद्र में भी सत्ता में है। ऐसे में संभव है कि उसे केंद्र सरकार से अधिक सहानुभूति पूर्ण व्यवहार मिल जाए। तमिलनाडु की नई सरकार भी टकराव वाले बयानों से बच रही है। लेकिन खुद केंद्र सरकार पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण गंभीर राजकोषीय संकट से जूझेगी और

उसके पास भी खर्च करने की सीमित क्षमता ही होगी। जो भी हो, नवनिर्वाचित राज्य सरकारों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डाले बगैर चुनावी वादे पूरे करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारत में चुनाव 'रेवड़ी' यानी मुफ्त के तोहफे बढ़ाने की उपजाऊ जमीन बन गए हैं। हर राजनीतिक दल सोचता है कि सत्ता में आने का इकलौता तरीका यही है और सब्सिडी या नकद रकम भेजने के लिए नए-नए तरीके ईजाद करता रहता है। सोलहवें वित्त आयोग ने नकद अंतरण की तेजी से बढ़ती इसी प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था, ' बिना शर्त नकद अंतरण 2018-19 और 2025-26 के बजट अनुमानों के दरम्यान 28.8 प्रतिशत की दर से बढ़े हैं।' उसने यह भी कहा, 'ज बिना शर्त अंतरण नए-नए इलाकों में तेजी से फैल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा राज्य इन्हें रकम देने का पसंदीदा साधन मानकर अपना रहे हैं।' सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए अपने घोषणापत्रों में बड़े-बड़े वादे करते रहे हैं और सत्ता में आते ही वे वादे उन्हें परेशान करने लगते हैं।केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की तीन नव निर्वाचित सरकारों की कहानी भी अलग नहीं है। इन तीनों राज्यों के पास ज्यादा राजकोषीय गुंजाइश नहीं है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व घाटे की बात करें तो अभी केरल के लिए यह 2.1 प्रतिशत है, जो उसके राजकोषीय घाटे का 77 प्रतिशत है। इसी तरह तमिलनाडु के लिए राजस्व घाटा 1.5 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल के लिए 2.4 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि उधार ली गई 50 से 70 प्रतिशत रकम राजस्व व्यय पूरे करने में खर्च हो रही है।इन राज्यों में राजस्व प्राप्तियों का लगभग 20 प्रतिशत ब्याज चुकाने में ही निकल जाता है। जीएसडीपी के अनुपात में बकाया देनदारियों की बात करें तो केरल में ये 37 प्रतिशत, तमिलनाडु में 30 प्रतिशत से अधिक और पश्चिम बंगाल में 40 प्रतिशत से अधिक थीं। सोलहवें वित्त आयोग के अनुसार केरल में बजट के अलावा भी उधारी ली गई है और मार्च 2025 में केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड पर भी लगभग 28,880 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था। तमिलनाडु में राज्य बिजली वितरण कंपनी पर ही 2023-24 में लगभग 1.73 लाख करोड़ रुपये कर्ज बकाया था।फिर भी मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाएं कम नहीं हो रहीं। तमिलगा वेट्री कषगम ने 40 बिंदुओं वाले अपने घोषणापत्र में हर महिला को 2,500 रुपये महीने देने, छह मुफ्त गैस सिलिंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, लड़कियों की शादी के लिए आठ ग्राम सोना और एक रेशमी साड़ी देने, नवजात के लिए सोने की एक अंगूठी देने, हर स्नातक को 4,000 रुपये और हर डिप्लोमा धारक को 2,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और हर परिवार के लिए 25 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा सहित अनेक वादे किए गए हैं। जब राज्य के बजट में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये की देनदारी बकाया हैं।

अबूझमाड़ के इरकभट्टी के आदिवासी ग्रामीणों के साथ बैठे मंत्री कश्यप

इरकभट्टी में बिना किसी भय के ग्रामीण जुटे और मंत्री केदार कश्यप के साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम सुना.

इमली के पेड़ तले की बातकी चौपाल

नारायणपुर। कोहकामेटा तहसील के ईरकभट्टी में रविवार को एक अनूठा और भावनात्मक दृश्य देखने को मिला, जब इमली के विशाल पेड़ की छांव के नीचे 'मन की बात' की चौपाल सजी। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप ने आदिवासी ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को सुना।

ईरकभट्टी के लिए यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा, क्योंकि यहां के ग्रामीण दिल्ली दूरदर्शन के लाइव प्रसारण में भी दिखाई दिए। इससे ग्रामीणों में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए। छोटे बच्चों ने भी पूरे ध्यान से प्रधानमंत्री के विचारों को सुना और कार्यक्रम का हिस्सा बने।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि एक समय था, जब इस क्षेत्र में नक्सलियों की जन अदालतें लगती थीं और ग्रामीण भय के वातावरण में जीवन जीने को मजबूर थे, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। विकास की रफ्तार ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है और अब ग्रामीण बिना किसी डर और भय के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री के विचार सुन रहे हैं।मन की बात कार्यक्रम के बाद मंत्री केदार कश्यप इरकभट्टी के घोटूल पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी समाज के पारंपरिक 'देवता शादी' कार्यक्रम में शिरकत की।

इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत देश की अमूल्य धरोहर है, जिसे संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।कोहकामेटा में आयोजित 'मन की बात' का यह चौपाल केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बदलते बस्तर और विकसित होते आदिवासी अंचल की नई कहानी बनकर उभरा। जिस क्षेत्र को कभी नक्सल प्रभाव के लिए जाना जाता था, वहीं आज विकास, लोकतंत्र और जनभागीदारी की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के संदेशों से प्रेरित ग्रामीणों का उत्साह यह दर्शाता है कि विकास की धारा अब दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच चुकी है और लोग सकारात्मक बदलाव के सहभागी बन रहे हैं।

बस्तर में समय से पहले दस्तक दे सकता है मानसून

जगदलपुर। भीषण गर्मी के बीच बस्तरवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस बार मानसून के बस्तर में सामान्य तिथि से पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की वास्तविक गति उसके आगे बढ़ने की स्थिति पर निर्भर करेगी।

मौसम विभाग के अनुसार, बस्तर में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि 13 जून मानी जाती है। पिछले 15 से 20 वर्षों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो मानसून लगभग इसी अवधि में पहुंचता रहा है. हालांकि, दो से चार दिनों का अंतर सामान्य माना जाता है। इस वर्ष केरल में मानसून की जल्द एंट्री को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बस्तर में भी मानसून तय समय से थोड़ा पहले पहुंच सकता है।

विभाग का कहना है कि यदि मानसूनी हवाएं मजबूत रहीं तो इसका असर बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि मानसून के आगमन की तिथि पूरी तरह उसकी गति और हवाओं की मजबूती पर निर्भर करती है। यदि हवाएं कमजोर पड़ती हैं तो मानसून की रफ्तार थम सकती है, जबकि हवाएं प्रबल होने पर यह तेजी से अधिक क्षेत्रों को कवर करते हुए पहले पहुंच सकता है।

फिलहाल, मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि बस्तर में मानसून की दस्तक सामान्य तिथि के आसपास ही रहेगी, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो इस बार बारिश का इंतजार थोड़ा पहले खत्म हो सकता है। ऐसे में किसानों समेत आम लोगों की नजरें अब मानसून की अगली गतिविधियों पर टिकी हुई हैं।

दो कॉलोनियों के बीच पहुंच मार्ग को लेकर विवाद

पूर्व महापौर पांडेय व बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बिलासपुर। शिवम एन्क्लेव और मिनोचा कॉलोनी के बीच स्थित रास्ते के पास सफाई कार्य के दौरान पहुंच मार्ग को लेकर 31 मई को हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सिविल लाईंस पुलिस ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व महापौर राजेश पांडेय और उनके पुत्र राहुल पांडेय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3), 126 (2) और 3 (5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता अमित शर्मा ने आरोप लगाया है कि 31 मई की सुबह शिवम एन्क्लेव और मिनोचा कॉलोनी के बीच स्थित रास्ते के पास सफाई कार्य चल रहा था। बताया गया कि सोसायटी की बैठक के बाद रहवासी और सफाई कर्मचारी मुख्य द्वार के आसपास सफाई कर रहे थे।

इसी दौरान करीब 10 बजे राजेश पांडेय और राहुल पांडेय वहां पहुंचे, जिसके बाद रास्ते को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान उनके साथ गाली-गलौज की गई। उन्होंने हाथ जोड़कर स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला और बढ़ गया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने उन्हें पकड़कर नीचे गिरा दिया और लात-घूंसों से मारपीट की।

शिकायतकर्ता के अनुसार उनके पैर पकड़कर जमीन पर गिराया गया और सिर तथा दाहिने कंधे पर पत्थर से हमला किया गया।

इस घटना में उन्हें चोटें आई और उनका चश्मा भी टूट गया। अमित शर्मा ने पुलिस को बताया कि लगभग दो महीने पहले उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था और वर्तमान में उनका इलाज एम्स में चल रहा है। वे मधुमेह और लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तथा उनके दाहिने हाथ का दो बार ऑपरेशन हो चुका है। आरोप है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी होने के बावजूद उनके साथ मारपीट की गई, जिससे चेहरे, पीठ, घुटनों और कंधे पर चोटें आईं।

शिकायत में जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। उनके पिता भी उसी क्षेत्र में रहते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका है। उन्होंने पुलिस सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

अभद्र टिप्पणी पर आदिवासी समाज का धरना

मतरी। शहर के सिटी कोतवाली थाना परिसर में सोमवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में थाना पहुंचकर धरने पर बैठ गए। समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि गरियाबंद निवासी संस्कार सतपति ने सोशल मीडिया पर आदिवासी समाज के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इस युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।

मामले में शिकायत दर्ज कराने और एफआईआर की मांग को लेकर आदिवासी समाज के सदस्य बड़ी संख्या में सिटी कोतवाली पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे नाराज होकर समाज के लोगों ने थाना परिसर के सामने ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वनवासी संबंधी बयान पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध दर्ज कराया। समाज के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।

धरना-प्रदर्शन के चलते थाना परिसर में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

ऑक्सीजन सपोर्ट पर पोलिंग बूथ पहुंचे बुजुर्ग, डाला वोट

बालोद। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच बालोद जिले के नगर पंचायत पलारी में मतदान के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।

यह तस्वीर उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है, जो छोटी-छोटी वजहों से मतदान केंद्र तक पहुंचने से बचते हैं। नगर पंचायत पलारी में चल रहे चुनाव के दौरान बुजुर्ग मतदाता हेमलाल साहू स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे। खास बात यह रही कि वे ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे मतदान केंद्र तक पहुंचे और मतदान किया। भीषण गर्मी के बीच ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ मतदान करने पहुंचे हेमलाल साहू की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता ने लोगों का दिल जीत लिया।

मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य मतदाताओं ने भी उनके जज्बे की सराहना की। हेमलाल साहू की यह पहल यह संदेश देती है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर वोट की अहम भूमिका होती है।

भाजपा नेता के साथ बदसलूकी के मामले में सीईओ रूपेश पाण्डेय निलम्बित

दुर्ग। सुशासन तिहार के तहत ग्राम थनौद में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में भाजपा नेता के साथ बदसलूकी के मामले में जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ रूपेश कुमार पाण्डेय को निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग महेन्द्र कुमार जांगड़े को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। दुर्ग संभागायुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह घटना विधायक ललित चंद्राकर की मौजूदगी में हुई थी और उन्होंने जनपद सीईओ की शिकायत की थी। जिसके बाद यह कार्यवाही की गई।

जारी आदेश के मुताबिक 30 मई को श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग के द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं अशिष्ट व्यवहार किए जाने के कारण निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर जिला दुर्ग से प्राप्त प्रस्ताव एवं शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार के तहत् ग्राम थनौद में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग द्वारा आम जनता से अशिष्ट व्यवहार संबंधी वीडियो क्लिप के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग के द्वारा शासन द्वारा आयोजित सुशासन विहार एवं शिविर में कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं आम जनता से अशिष्टतापूर्वक व्यवहार किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आवरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1578/आयुक्त/स्थापना/2026 दिनांक 30 मई, 2026 द्वारा श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके सदर्भ में श्री पाण्डेय के द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं है। छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा, कर्तव्यपरायण रहेगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कि शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो एवं नियम 3-क के खण्ड (क) के अनुसार कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नही करेगा, उपबंधित है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जल जीवन मिशन के तहत लरघाडंडी में हर घर पहुंचा पानी

एमसीबी। जल जीवन मिशन जिले की विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत दूधांसी के आश्रित ग्राम लरघाडंडी में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण जीवन की तस्वीर बदल दी है। कभी पेयजल संकट से जूझने वाला यह गांव आज नियमित जलापूर्ति, जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभर रहा है। एक समय था जब ग्रामीणों को पानी की एक-एक बूंद के लिए हैंडपंप, कुओं और नदी पर निर्भर रहना पड़ता था। महिलाओं और बुजुर्गों को दूर-दूर तक पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था, जिससे समय और श्रम दोनों की बड़ी खपत होती थी। लेकिन अब जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से गांव में यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विकसित जल स्रोत, 10 हजार लीटर क्षमता की पानी टंकी तथा मोटर पंप आधारित जलापूर्ति व्यवस्था के माध्यम से गांव में नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बिछाई गई पाइपलाइन के जरिए अब हर घर तक पानी पहुंच रहा है।

खेत बचाओ अभियान को मिल रहा जनसमर्थन, जैविक खेती

बलरामपुर। जिले में खेत बचाओ अभियान के माध्यम से किसानों को मृदा संरक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य खेतों की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखते हुए टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है। जिले में किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक एवं असंतुलित उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की जैविक सक्रियता कम होती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तथा भूमि की उत्पादक क्षमता प्रभावित होती है। इसके साथ ही पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट, जैविक खाद तथा नील हरित शैवाल जैसे प्राकृतिक विकल्पों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ने, भूमि की संरचना में सुधार करना है।

चोरी के 16 मामलों में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 गिरफ्तार

कांकेर। जिले की पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुए चोरी के 16 मामलों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों जगदीश बंजारा, परमेश्वर राठौर एवं मंहगू मरकाम को गिरफ्तार करते हुए लाखों का चोरी का सामान जब्त किया गया। पुलिस ने इस दौरान कांकेर जिले में लगातार सोलर पंप, सोलर प्लेट पैनल, स्टार्टर एवं केबल वायर चोरी की घटनाओं पर लगाम लगा है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में अपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें थाना नरहरपुर,चौकी दुधावा,चौकी हल्बा,थाना चारामा में 16 मामलों में धारा 303(2) के अंतर्गत मामला सिद्ध होने पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि पिछले लगभग 6 से 8 माह के दौरान थाना नरहरपुर, चौकी दुधावा, चौकी हल्बा तथा थाना चारामा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में किसानों एवं सिंचाई कार्यों में उपयोग किए जाने वाले सोलर प्लेट पैनल सिस्टम, सोलर पंप, स्टार्टर एवं केबल वायर की लगातार चोरी हो रही है।

सुकमा में दो समूह के बीच हिंसक झड़प में 13 घायल

सुकमा। जिले के साडरापाल गांव में दो समूह के बीच हिंसक झड़प होने से 13 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस इस मामले में दस ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। सुकमा पुलिस ने इस घटना को जमीन विवाद और आपसी विवाद की परिणति बताया है। पुलिस के अनुसार घटना जिसमें आरोपियों ने लामबंद होकर मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में धारा 191 (2), 191 (3), 190, 296, 351(2),115(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर में हड़मा मांडवी, गंगाराम कवासी, बुधरा कवासी, महादेव कवासी, हनीस करटामी, आयता कवासी, लच्छु कवासी, हांदा वेट्टी, गुड्डी राम बेट्टी और सन्ना आयता के नाम आरोपी के रुप में दर्ज है। आधिकारिक रुप से दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि, इस घटना में कोई गंभीर रमप से घायल नहीं है। यह सामान्य मारपीट का मामला है। वहीं इस घटना को छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फ़ोरम ने ईसाईयों पर हमला बताते हुए कहा है कि मिट्टी के घर में ईसाईजन की प्रार्थना कर रहे थे।

उत्कर्ष योजना की 26 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा फिलहाल टली

एमसीबी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के अंतर्गत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया एवं आबंटित संस्थाओं के इम्पैनलमेंट कार्य में विलंब होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 26 जुलाई 2026, रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा अब निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं होगी। कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास), एमएस बी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को इस संबंध में सूचित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का आवेदन जमा नहीं किया जाए। अधिकारियों के अनुसार आवंटित संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश पृथक रूप से जारी की जाएगी।

नगर पालिका अध्यक्ष ने कलेक्टर से की सीएमओ की शिकायत

आरंग। नगर पालिका परिषद आरंग में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी अब एक बड़े राजनैतिक-प्रशासनिक विवाद के रूप में सामने आई है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सीएमओ शीतल चंद्रवंशी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए धरातल पर काम होने का दावा किया है। इस खींचतान के बाद आरंग की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन ने कलेक्टर को सौंपे गए पत्र में सीएमओ पर शासन के निर्देशों की अनदेखी और निर्वाचित परिषद को दरकिनार करने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष का कहना है कि 08 मई को 'सुशासन तिहार' के तहत आयोजित समाधान शिविर में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने वार्ड क्रमांक 13 में अधूरे पड़े मिनी माता स्मृति भवन की समीक्षा की थी। मंत्री ने मंच से निर्देश दिए थे कि यदि ठेकेदार 2 दिनों में काम शुरू नहीं करता तो टेंडर निरस्त कर नया टेंडर जारी किया जाए। डॉ. जैन का आरोप है कि कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी न काम शुरू हुआ और न ठेकेदार पर कार्रवाई की गई, जिससे जनता में शासन की छवि धूमिल हो रही है।

नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट 31 मार्च 2026 तक प्रस्तुत होना था, जिसके लिए उन्होंने 16 मार्च को ही लिखित निर्देश दिए थे, परंतु प्रशासन की ढिलाई के कारण यह बजट देरी से 27 अप्रैल की सामान्य सभा में पेश हो सका। अध्यक्ष का आरोप है कि एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) योजना के तहत आवास आवंटन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को उनकी अनुपस्थिति में पूरा किया गया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रोटोकॉल के लिहाज से अनुचित है। इस पूरे विवाद पर जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) शीतल चंद्रवंशी से बात की गई तो उन्होंने अध्यक्ष के तेवरों और आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रशासनिक व तकनीकी पक्ष सामने रखा। सीएमओ शीतल चंद्रवंशी ने साफ किया कि मिनीमाता स्मृति भवन को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत है। धरातल पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है और वर्तमान में वहां सेप्टिक टैंक का स्लैब डालने का कार्य भी पूरा होने जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, किसी भी चालू ठेके को अचानक निरस्त करने की एक लंबी कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया होती है। इसमें एस्टीमेट का पुनर्मूल्यांकन और नियमानुसार नोटिस अवधि देना अनिवार्य होता है, ताकि मामला अदालती दांव-पेच में न फंसे। प्रशासन ने नियमों के दायरे में रहकर ठेकेदार से काम शुरू करवाया है। बजट और आवास आवंटन जैसे बड़े कार्यों में विभागीय स्वीकृतियों, कड़े सरकारी नियमों, स्क्रूटनी (दस्तावेजों की जांच) और प्रशासनिक व्यस्तताओं के चलते कई बार समय-सीमा में व्यावहारिक बदलाव आ जाते हैं।

पीएम आवास पर 3 माह से ब्रेक

कलेक्टर ने मांगी रिपोर्ट, कहा- जांच के बाद होगा निराकरण

मुंगेली। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही द्वारा प्रशासनिक प्रताड़ना के लगाए गए आरोपों के बाद यह मामला अब राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। हितग्राही विमला बाई एवं उनके परिजनों का कहना है कि निर्माण कार्य पर स्टे लगाए जाने के तीन महीने बाद भी स्थानीय राजस्व अमला यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि वह अपनी निजी भूमि पर मकान बना रहा है या फिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है।शिकायतकर्ताओं का दावा है कि वह मौके पर मौजूद अपनी 13 डिसमिल निजी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा रहा है। यदि जांच में यह साबित हो जाए कि सरकारी जमीन पर एक इंच भी निर्माण हुआ है तो प्रशासन को बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वयं निर्माण हटाने को तैयार है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राजस्व विभाग इस विवाद का अंतिम निराकरण नहीं कर सका।

शिकायतकर्ता देवेंद्र एवं उनके परिजनों के अनुसार अब तक 8 बार जांच टीम मौके पर पहुंच चुकी है और 3 बार सीमांकन भी कराया जा चुका है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि निर्माण निजी भूमि पर है या शासकीय भूमि पर। इसी वजह से वह लगातार दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हुआ।

संक्षिप्त समाचार

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेशभर में चला नशामुक्ति जागरूकता अभियान

रायपुर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर

पर प्रदेशभर में नशामुक्ति एवं जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर द्वारा व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर श्रीमती विनीता वार्नर के मार्गदर्शन तथा सचिव सुश्री पायल टोपनो के निर्देशन में संपन्न हुआ। अभियान के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जनसंवाद आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। थानों में नियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा विभिन्न स्थानों पर लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। मुख्य कार्यक्रम सबरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र सूरजपुर एवं ग्राम नमदगिरि में आयोजित किया गया। इसके अलावा वृद्धाश्रम सूरजपुर, गणेशपुर बाजार, थाना परिसर चांदनी, थाना परिसर प्रेमनगर सहित ग्राम बारगीडीह, बड़सरा, डुमरिया, दवाना, कुरुवां, केवड़ा और हर्राटिकरा में भी जागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने व्यावसायिक परिसर का किया लोकार्पण

रायपुर। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक श्री अरुण साव ने सोमवार को लोरमी के ग्राम पंचायत अमलडीही में नवनिर्मित व्यावसायिक परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह परिसर स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीणों के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करेगा। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार का संकल्प गांवों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। जनसुविधाओं के विस्तार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास निरंतर जारी है।

बेमेतरा सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था, दुर्ग संभागायुक्त करेंगे जांच

रायपुर/बेमेतरा। बेमेतरा में जिले में रविवार को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग संभागायुक्त से जांच कर रिपोर्ट मांगी है। हालांकि मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बेमेतरा जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन आंधी-तूफान की वजह से कार्यक्रम स्थल को बदलना पड़ा। कलेक्टर ने कार्यक्रम से पहले उनसे चर्चा की थी। इस कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू सहित 23 जोड़ों ने विवाह किया था।

बदरा जलाशय के बांध और नहर के कार्यों के लिए 4.17 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने कोरिया जिले के विकासखण्ड सोनहत स्थित बदरा जलाशय के बांध एवं नहर के नवीनीकरण कार्य के लिए 4 करोड़ 17 लाख 75 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने पर क्षेत्र के किसानों को 355 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे खरीफ और रबी दोनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। योजना के अंतर्गत कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग ने कार्य को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बदरा जलाशय के नवीनीकरण से क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और भू-जल स्तर में भी सुधार होने की संभावना है।

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन रायपुर के अध्यक्ष बने डॉ. पीयूष श्रीवास्तव

रायपुर। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन रायपुर

के अध्यक्ष पद पर डॉ. पीयूष श्रीवास्तव निर्वाचित हुए है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि डॉ. पीयूष के नेतृत्व में संगठन चिकित्सकों, रेजिडेंट डॉक्टरों एवं मेडिकल छात्रों के हितों की रक्षा के लिए और अधिक मजबूती से कार्य करेगा। डॉ. पीयूष श्रीवास्तव इस मजबूत आधार को आगे बढ़ाते हुए संगठन को नई सफलताओं तक ले जाएंगे तथा चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी नेतृत्व प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन चिकित्सकों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा। इस अवसर पर डॉ. लोधी ने जेडीए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रेशम सिंह के ऐतिहासिक, संघर्षशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल ने जेडीए रायपुर को नई दिशा, नई पहचान और नई ऊर्जा प्रदान की है।

राजभवन (लोक भवन) में बालिका गृह की बेटियों से राज्यपाल रमेन डेका ने किया आत्मीय संवाद

जीवन में ऐसा कार्य करें जिसमें केवल पाना नहीं, समाज को कुछ देना हो

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने सोमवार को लोक भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में एसओएस बालिका गृह, माना की बालिकाओं से आत्मीय संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने अंगदान एवं देहदान का संकल्प लेकर मानवता की सेवा का अनुकरणीय संदेश देने वाले 75 नागरिकों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने बालिका गृह की बेटियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे समाज और राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य हैं। शिक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और कड़े परिश्रम के बल पर जीवन में कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बालिकाओं से अपने सपनों को कभी छोटा न समझने और निरंतर सीखते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने कहा कि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट पर उपलब्ध बहुत सी जानकारियां समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन पुस्तकों में संचित ज्ञान लंबे समय तक हमारा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने बालिकाओं को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने की सलाह दी। विशेष रूप से सफल विभूतियों की जीवनी पढ़ने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे यह समझने का अवसर मिलता है कि कैसे कठिन संघर्षों और निरंतर प्रयासों के बाद लोग सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। ऐसी प्रेरक कहानियां जीवन में आगे बढ़ने का साहस और संकल्प देती हैं। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि जीवन में हमेशा ऐसा कार्य करने का प्रयास करें जिसमें केवल पाने की लालसा न हो, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज के कल्याण में योगदान देने का निस्वार्थ भाव हो। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं से सीधे बातचीत कर उनकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों के आत्मीय जवाब दिए। उन्होंने बालिकाओं को उपहार स्वरूप स्टेशनरी सामग्री भेंट की, वहीं बालिकाओं ने भी राज्यपाल को स्व-निर्मित उपहार भेंट कर अपना स्नेह व्यक्त किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने पर्यावरण एवं जल संकट के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मानव, पशु एवं प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस संतुलन को कायम रखने में वृक्षों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए पेड़ों को बचाना और व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

राज्यपाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ष्हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन पानी भी खरीदकर पीना पड़ेगा। इसलिए जल का संवर्धन और संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि हमने आज पेड़ों को नहीं संभाला, तो आने वाले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ को गंभीर भू-जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इंसान ही स्वच्छ हवा और पानी को प्रदूषित कर रहा है, इसलिए इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी इंसान की ही है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ने से कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। इसी प्रकार, चिकित्सा शिक्षा और शोध के क्षेत्र में देहदान का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि जो लोग अंगदान और देहदान का संकल्प ले रहे हैं, वे समाज के सच्चे नायक हैं। उन्हें अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यह संवेदनशीलता और मानवता का सबसे उच्च भाव है, जिसे हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में राज्यपाल ने अंगदान एवं देहदान का संकल्प लेने वाले 75 नागरिकों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही, रायपुर जिले के कलेक्टर श्री गौरव सिंह को भी इस पुनीत क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा दुबे सहित राजभवन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी, अंगदान व देहदान का संकल्प लेने वाले प्रबुद्ध नागरिक, बालिका गृह की बालिकाएं तथा उनके शिक्षक उपस्थित थे।

साय का कड़ा संदेश: जनता से अशिष्ट व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में आम जनता से अशिष्ट व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रूपेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दुर्ग संभागायुक्त को दिए थे। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशों के परिपालन में कमिश्नर दुर्ग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग, श्री रूपेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

संभागायुक्त दुर्ग द्वारा जारी निलंबन आदेश में उल्लेखित है कि कलेक्टर दुर्ग से प्राप्त प्रस्ताव एवं ग्राम थनौद में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में श्री पाण्डेय द्वारा आम जनता से अशिष्ट व्यवहार संबंधी वीडियो क्लिप के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार एवं शिविर में कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही तथा अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत है। इस संबंध में संभागायुक्त दुर्ग द्वारा श्री पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक को सदैव पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण रहना है तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो। नियम 3-क के खण्ड (क) के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन तंत्र आम नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए प्रत्येक लोकसेवक द्वारा आम नागरिकों से शिष्ट व्यवहार को आचरण संहिता का महत्वपूर्ण घटक माना गया है।

केदार के सख्त निर्देश, देरी पर होगी कार्रवाई

वन विभाग में 'विभागीय जांच की सुस्ती' पर एक्शन

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग में वर्षों से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों को आगामी तीन माह के भीतर अनिवार्य रूप से निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के बाद यदि पुराने प्रकरण असामान्य अथवा अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो संबंधित जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, वन विभाग को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

वन मंत्री ने कहा कि विभागीय जांच मामलों में अनावश्यक देरी न केवल प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाती है, बल्कि इससे कर्मचारियों को वर्षों तक मानसिक, सामाजिक एवं सेवा संबंधी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में निर्णयहीनता और अनावश्यक विलंब के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

कश्यप ने कहा कि कई मामलों में विभागीय जांच प्रस्ताव 4-5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि कुछ प्रकरण संबंधित अधिकारी अथवा

कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भेजे जाते हैं। उन्होंने इसे सुशासन, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन की भावना के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक प्रकरण लंबित रहने से न केवल अभिलेखों और साक्ष्यों के परीक्षण में कठिनाई आती है, बल्कि विभागीय कार्यवाही की गंभीरता और प्रभावशीलता भी कमजोर होती है। कई कर्मचारी वर्षों तक बिना निर्णय की स्थिति में कार्य करने को विवश रहते हैं, जिससे उनके सेवा हित, पदोन्नति, पेंशन एवं व्यक्तिगत जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वन मंत्री ने कहा, न्याय में विलंब, न्याय से वंचित करने के समान है। यदि कोई कर्मचारी दोषी है तो समय पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि निर्दोष है तो उसे अनिश्चितता एवं अनावश्यक उत्पीड़न से शीघ्र राहत मिलनी चाहिए,

वन मंत्री केदार कश्यप ने निर्देश दिए हैं कि एक माह के भीतर विभाग में पूर्व से लंबित सभी विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी संकलित की जाए तथा सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय किए बिना प्रशासनिक सुधार संभव नहीं है। विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सुशासन की मूल आवश्यकता है। वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुशासन, समयबद्ध निर्णय और जवाबदेह कार्यसंस्कृति पर दिए जा रहे विशेष बल के अनुरूप वन विभाग में भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाया जा रहा है।

कश्यप ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें कर्मचारियों को समय पर न्याय मिले, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हो और जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय हो।

तहसीलदारों की हड़ताल पर समाधान की उम्मीद: राजस्व मंत्री

- टंक राम वर्मा बोले- सचिव स्तर पर हो रही चर्चा, जल्द निकलेगा रास्ता

रायपुर। सीतापुर की घटना के बाद तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के आंदोलन को लेकर सरकार और राजस्व अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के सरकारी निवास पर कनिष्ठ प्रशासनिक संघ और राजस्व विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी भी मौजूद रहीं।

बैठक के दौरान तहसीलदार संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों और आपत्तियों को सरकार के सामने रखा। वहीं, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा।

बता दें कि सरगुजा जिले के सीतापुर में भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों द्वारा नायब तहसीलदार तुषार मानिक की कथित पिटाई के बाद, राज्य के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल और सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। राजस्व अधिकारियों ने मुख्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित

राजस्व अधिकारियों ने आज से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल और कामबंद आंदोलन शुरू कर दिया है।

मीडिया से बातचीत में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग की सचिव तहसीलदार संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राजस्व सचिव उनसे बात कर रहे हैं। जो भी हुआ है, उसका समाधान हो जाएगा। तहसील अधिकारी काम पर लौट आएंगे और स्थिति सामान्य हो जाएगी।

बताया जा रहा है कि सीतापुर में हुई घटना को लेकर तहसीलदार संघ संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर संघ के प्रतिनिधि राजस्व मंत्री और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी संघ से सीधी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सचिव स्तर पर लगातार संवाद जारी है और जल्द ही इसका निराकरण कर लिया जाएगा।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के साथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, भाजपा सरकार का नारा सबका साथ, सबका विकास है। सभी के साथ न्याय होगा और जो भी समस्या है, उसका समाधान निकाला जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के द्वारा बेमेतरा सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था पर अधिकारियों को फटकार लगाने के वायरल वीडियो को लेकर पूछे गए सवाल पर भी टंक राम वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डॉ. रमन सिंह एक अनुभवी और सुलझे हुए नेता हैं, जो परिस्थितियों को भलीभांति समझते हैं।

मंत्री ने कहा, अतिथियों की गरिमा के अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए थी। विधानसभा अध्यक्ष परिस्थितियों को देखकर ही अपनी बात रखते हैं। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने जो कहा, वह परिस्थितियों के अनुरूप कहा है।

राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि जब शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तब स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्ती या कार्रवाई करना उचित है। उन्होंने कहा, दिक्कत तब होती है जब शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अड़ंगा लगता है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आम पेड़ के नीचे लगाई चौपाल

रायपुर। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साव ने सोमवार को लोरमी के ग्राम जरहापारा में आम पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने इस दौरान गांव में हुए विकास कार्यों पर चर्चा कर जनकल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने जरहापारा में देवगुड़ी निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साव ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान किया। उन्होंने ग्रामीणों के आवेदनों के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि डबल इंजन की सरकार वनांचलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जनमन योजना एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से वन ग्रामों को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।

पीडब्ल्यूडी सचिव ने सभी अभियंताओं की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की

स्वीकृत कार्यों के 30 जून तक निविदा आमंत्रित कर 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विभागीय मुख्यालय 'निर्माण भवन' में आयोजित बैठक में अधिकारियों को मार्च-2026 तक स्वीकृत कार्यों के 30 जून तक निविदा आमंत्रित कर 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा ऋतु के तुरंत बाद ये काम शुरू किए जा सकें।

उन्होंने छत्तीसगढ़ से गुजर रहे भारतमाला परियोजनाओं की सड़कों से राज्य की सड़कों को जोड़ने फोरलेन सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना बनाने को कहा, ताकि भारतमाला सड़कों का पूरा लाभ राज्य को भी मिल सके। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव भी बैठक में मौजूद थे। विभाग के सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल प्रदेशभर की 36 द्रुतगामी सड़कों के साथ ही दूरस्थ अंचलों के पहुंचविहीन गांवों के लिए भी प्राथमिकता से सड़कों व पुलों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कार्यों की प्राथमिकता सूची तैयार कर 10 जून तक भेजने को कहा। उन्होंने 31 जुलाई तक इनके प्राक्कलन भी भेजने के निर्देश दिए। श्री बंसल ने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में आर.सी.पी.एल.डब्लू.ई.ए. (Road Connectivity Project in Left Wing Extremism Areas) के कार्यों को हर हाल में 31 मार्च 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद अधिकारियों को जिओ-टैगिंग और एसएनए का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया।

श्री बंसल ने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण कर समय पर उनका

भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों के देयकों का भुगतान एक माह के भीतर करने को कहा। उन्होंने भुगतान के पहले सभी कार्यों का कड़ाई से सत्यापन भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक किए गए कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र और फाइनल बिल समीक्षा के लिए भेजने को कहा। श्री बंसल ने सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को हर तीन महीने में राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

विभागीय सचिव ने निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों से अच्छा समन्वय रखकर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा में कार्य पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को डामरीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान खुद फील्ड में मौजूद रहकर कड़ी निगरानी रखने को कहा।

उन्होंने सभी अधिकारियों को हर मंगलवार को अपने कार्यालय में ही रहने के निर्देश दिए। उन्होंने काम में ढिलाई एवं लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर नियमानुसार कार्यवाही करने को भी कहा। उन्होंने भू-अर्जन के मामलों में मिशन मोड में काम करते हुए आगामी तीन से छह माह के भीतर सभी प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बरसात को देखते हुए सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर पूर्ण करने को कहा।

श्री बंसल ने कार्यों में सुविधा और प्रशासनिक कसावट के लिए विभाग के विभिन्न अनुविभागीय कार्यालयों के स्थानांतरण एवं पुनर्गठन की कार्यवाही जून कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में लोक विर्माण विभाग की परिसंपत्तियों के डिजिटाइजेशन, एसडीओ से लेकर प्रमुख अभियंता कार्यालय तक ई-ऑफिस से कार्य संपादित करने, कार्यालयों को सुव्यस्थित रखने, गति शक्ति पोर्टल पर कार्यों की प्रगति की जानकारी समय पर अपडेट करने, न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब समय पर दाखिल करने, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद तकनीकी स्वीकृति, निविदा आमंत्रण और कार्यादेश जारी करने की प्रक्रियाएं दो से तीन माह में पूर्ण करने तथा चालू वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत कराने के भी निर्देश दिए।

क्या क्षेत्रीय दलों का दौर अब ढलान पर है?

श्याम यादव

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिणाम के बाद देश की राजनीति एक बार फिर अपने बदलते स्वरूप को लेकर चर्चा में है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका और उनकी राजनीतिक पकड़ को लेकर नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय राजनीति धीरे-धीरे राष्ट्रीय दलों के केंद्र में सिमटती जा रही है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका लंबे समय तक निर्णायक रही है। एक समय ऐसा था जब केंद्र की सत्ता तक पहुँचने के लिए किसी भी राष्ट्रीय दल को क्षेत्रीय दलों के समर्थन की जरूरत पड़ती थी। गठबंधन सरकारों का दौर इसकी सबसे बड़ी मिसाल रहा है। नब्बे के दशक से लेकर दो हजार के शुरुआती वर्षों तक तेलुगू देशम पार्टी, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, समाजवादी दल, वामपंथी दल, जनता दल और अन्य क्षेत्रीय ताकतें केंद्र की राजनीति का संतुलन तय करती थीं। उस समय सरकारें अक्सर क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर ही खड़ी होती थीं। लेकिन पिछले एक दशक में यह राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलता दिखाई दिया है। भाजपा के लगातार विस्तार ने कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की स्थिति को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और असम जैसे राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदले हैं और कई क्षेत्रीय दल या तो कमजोर हुए हैं या सीमित प्रभाव तक सिमट गए हैं। एक समय अकाली दल, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, असम गण परिषद, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी क्षेत्रीय ताकतें राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। लेकिन आज इनकी भूमिका अधिकतर राज्य स्तर तक सीमित होती दिखाई दे रही है। भाजपा का विस्तार केवल हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसने पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने संगठन को पुनर्गठित करने की कोशिश में जुटी है, जिससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अधिकतर दो राष्ट्रीय ध्रुवों के बीच केंद्रित होती दिखाई दे रही है। हालाँकि इसका यह अर्थ नहीं है कि क्षेत्रीय दल पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। दक्षिण भारत में क्षेत्रीय पहचान, भाषा और स्थानीय मुद्दों का प्रभाव आज भी राजनीति को गहराई से प्रभावित करता है। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों की वह निर्णायक भूमिका, जो कभी गठबंधन सरकारों के दौर में दिखाई देती थी, अब पहले जैसी नहीं रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश धीरे-धीरे दो प्रमुख राजनीतिक ध्रुवों की दिशा में बढ़ रहा है, जहाँ एक ओर भाजपा और दूसरी ओर कांग्रेस प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रही हैं। क्षेत्रीय दल या तो इन दोनों में से किसी एक धुरी के साथ जुड़ते नजर आ सकते हैं या फिर अपने-अपने राज्यों तक सीमित रह सकते हैं। हालाँकि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में पूरी तरह दो दलीय व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ समीकरण तेजी से बदलते रहे हैं। कभी कांग्रेस का एकछत्र प्रभाव था, फिर गठबंधन युग आया और अब भाजपा का विस्तार दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि राजनीति एक स्थिर ढांचे में नहीं रहती, बल्कि लगातार परिवर्तनशील रहती है। बंगाल का हालिया राजनीतिक परिदृश्य केवल एक राज्य की घटना नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक परिवर्तन का संकेत भी है जो भारतीय राजनीति के स्वरूप को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत वास्तव में दो ध्रुवों की राजनीति की ओर बढ़ता है या फिर क्षेत्रीय दल एक बार फिर किसी नए राजनीतिक संतुलन की नींव रखते हैं।

पंजाब निकाय चुनाव के सियासी मायने

कमलेश पांडे

पंजाब के त्रिस्तरीय शहरी निकाय चुनाव- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत- सिर्फ स्थानीय सत्ता का संघर्ष नहीं हैं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रशासनिक चुनाव नहीं हैं, बल्कि ये पंजाब की बदलती क्षेत्रीय राजनीति, राष्ट्रीय दलों की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संघीय लोकतांत्रिक छवि से भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि 2026 के इन चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट माना जा रहा है।

पंजाब नगर निकाय चुनाव 2026 के चुनाव आयोग और मतगणना से जुड़े अब तक के मुख्य आंकड़े निम्नलिखित हैं- कुल 102 शहरी निकायों- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों- में चुनाव हुए, जहां मतदान प्रतिशत लगभग 63.94% दर्ज किया गया। नगर पंचायतों में सबसे अधिक 76.18% मतदान हुआ। नगर निगम क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 59.91% मतदान दर्ज हुआ। नगर परिषदों में लगभग 65.06% मतदान हुआ। कुल 1,896 वार्डों के लिए मतदान कराया गया। लगभग 7,555 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 79 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए।

इस चुनाव में अब तक आए नतीजों और घोषित रुझानों के अनुसार आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। आप ने लगभग 886 वार्ड जीते। जबकि कांग्रेस ने लगभग 358 वार्ड जीते। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 191-192 वार्ड, भाजपा को 172 वार्ड, बसपा को 7 वार्ड, और निर्दलीय उम्मीदवारों को 251 वार्ड पर जीत मिली। वहीं सीट प्रतिशत के हिसाब से मोटे अनुमान के मुताबिक, आप ने लगभग 50% के आसपास वार्ड, कांग्रेस ने लगभग 20% वार्ड, एसएडी ने लगभग 9ब वार्ड, बीजेपी ने लगभग 7% वार्ड और बीएसपी सहित अन्य ने लगभग 14% सीटो पर जीत व बढ़त हासिल की है।

जहाँ तक वोट प्रतिशत का सवाल है, तो विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और संकलित रुझानों के अनुसार दल और अनुमानित वोट प्रतिशत इसप्रकार हैं- आम आदमी पार्टी को लगभग 41-44%, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 24-27%, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 13-

16%, शिरोमणि अकाली दल को लगभग 10-13% और निर्दलीय व अन्य लगभग 5-8% वोट हासिल हुए हैं। इस प्रकार आप का वोट शेयर सबसे अधिक रहा, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर, शिरोमणि अकाली दल तीसरे नम्बर पर रही और इसने ग्रामीण-सिख बेल्ट में कुछ आधार वापस पाया, जबकि बीजेपी चौथे स्थान पर जाकर कुछ शहरी पॉकेट्स तक सीमित रही। आधिकारिक वोट प्रतिशत का सबसे विश्वसनीय डेटा sec.punjab.gov.in पर उपलब्ध है।

अब जिस तरह से इन चुनावों के नतीजे आए हैं, उसने यह तय कर दिया है कि राज्य की राजनीति में आम आदमी पार्टी की जमीन मजबूत हो रही है और कांग्रेस, भाजपा, एसएडी जैसे विपक्षी दल बचाव की मुद्रा में आ चुके हैं। लिहाजा पंजाब त्रिस्तरीय शहरी निकाय चुनाव के दलगत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सियासी मायने अहम हैं।

पहला, आप अपने जनविश्वास की परीक्षा में सफल: मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव सत्ता में आने के बाद शहरी जनसमर्थन मापने का अवसर था, जो बड़ी जीत के साथ उम्मीदों पर खरा उतरा। निकायों में मजबूत जीत मिली है। इससे यह संदेश गया कि पंजाब में आप सिर्फ वैकल्पिक प्रयोग नहीं, बल्कि स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। आप की बड़ी जीत इसी ओर संकेत करती है। आप के लिए ये चुनाव सबसे अहम थे क्योंकि वह राज्य की सत्ता में है। नगर निकायों में मजबूत प्रदर्शन से यह संदेश गया कि जनता अभी भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर भरोसा कर रही है। इसमें आप के लिए फायदे की बात यह है कि शहरी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत होने से दिल्ली मॉडल की तरह पंजाब मॉडल को भी प्रचारित करने का अवसर मिला। साथ ही विपक्ष के बिखराव का भी लाभ मिला। वहीं, आप के लिए खतरे की बात यह है कि नशा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक दखल के आरोप बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

दूसरा, कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई पर विपक्षी हैसियत बनाई- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए पंजाब आखिरी बड़े राज्यों में से एक है जहाँ वह अब भी राजनीतिक पुनर्जीवन की उम्मीद देखती है। वह मिली भी और पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी की हैसियत पा गई। भले ही कांग्रेस ने निकाय चुनावों में कमजोर प्रदर्शन किया, लेकिन इतनी सीट मिल गई कि उसका संगठनात्मक संकट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पंजाब कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, लेकिन लगातार संगठनात्मक कमजोरी और गुटबाजी ने उसे कमजोर किया है। फिर भी कांग्रेस के लिए अवसर यह है कि कई शहरों में दूसरे स्थान पर भी उसने मजबूत उपस्थिति दिखाई है, और वह खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित कर चुकी है, जबकि आगे शहरी असंतोष को भुनाने का मौका मिलेगा।

तीसरा, अकाली दल के पुनर्जीवन का संघर्ष बढ़ा- शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन और पुराने सत्ता-विरोधी माहौल के बाद अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन चुनावों ने बता दिया कि पंजाबियत और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति अभी कितनी प्रभावी है। शिरोमणि अकाली दल के लिए ये चुनाव राजनीतिक पुनर्जीवन की परीक्षा थे और आगे भी रहेंगे। किसान आंदोलन और पुराने भ्रष्टाचार आरोपों के बाद पार्टी जो कमजोर हुई थी, वह स्थिति नहीं बदली है।

लिहाजा अब वह खुद को पंजाबियत और क्षेत्रीय अस्मिता की पार्टी के रूप में फिर स्थापित करना चाहती है। शिरोमणि अकाली दल के लिए सकारात्मक संकेत यह है कि ग्रामीण-सिख वोट बैंक में आंशिक वापसी हुई, जो भाजपा से अलग होकर स्वतंत्र पहचान मजबूत करने की कोशिश हो सकती है, जबकि उसकी चुनौती यह है कि शहरी क्षेत्रों में कमजोर संगठन के चलते युवा मतदाताओं के बीच सीमित आकर्षण है।

चौथा, भाजपा के विस्तार की प्रयोगशाला- भारतीय जनता पार्टी पंजाब में शहरी हिंदू वोट और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के सहारे धीरे-धीरे विस्तार करना चाहती है। इसमें वह सफल रही। भाजपा नगर निकायों में सीटें ज्यादा नहीं बढ़ा पाई है, लिहाजा वह 2027 में गठबंधन राजनीति के बिना भी अधिक आक्रामक रणनीति अपना सकती है। भाजपा के लिए पंजाब अभी भी विस्तार का राज्य है। पार्टी हिंदू-शहरी वोट और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के सहारे जगह बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहां भाजपा के लिए अवसर यह है कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की कमजोरी का लाभ मिलेगा और शहरी निकायों में सीटें बढ़ाकर दीर्घकालिक आधार तैयार करने में सहूलियत होगी। हालांकि सबसे बड़ी बाधा किसान आंदोलन के बाद ग्रामीण पंजाब में अविश्वास। के चलते राज्य में अभी भी सीमित संगठनात्मक नेटवर्क है।

पांचवां, पंजाब में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़कर दलित वोट बैंक को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, जो इस बार भी नहीं मिली। क्योंकि वहां बड़ी दलित आबादी होने के कारण बीएसपी भविष्य की राजनीति में किंगमेकर की भूमिका देख रही है। लिहाजा इन चुनावों से उभरते बड़े संकेत इस बात की तस्दीक करते हैं कि पंजाब की राजनीति अब पूरी तरह बहुकोणीय हो चुकी है। शहरी मतदाता विकास के साथ-साथ नशे और प्रशासनिक जवाबदेही को भी अहम मुद्दा मान रहा है।

पंजाब के त्रिस्तरीय निकाय चुनावों ने तीन बड़े संकेत दिए हैं जिनके क्षेत्रीय मायने स्पष्ट हैं- पहला, पंजाब की राजनीति अब स्थायी रूप से बहुकोणीय हो चुकी है। दूसरा, आप फिलहाल मजबूत हुई है, लेकिन विपक्ष समाप्त नहीं हुआ। तीसरा, पंजाब की राजनीति अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष, संघीय लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजनीति से भी जुड़ चुकी है, जिसके क्षेत्रीय फायदे भी दिखेंगे।

चौथा, इन चुनावों से ऐसा प्रतीत हुआ है कि स्थानीय मुद्दों पर क्षेत्रीय जनमत हावी है। यही वजह है कि इस बार सिर्फ सड़क, पानी और सफाई ही नहीं, बल्कि बेरोजगारी, नशा, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा बने। कई जगह मतदाताओं ने जवाबदेही की मांग की। पांचवां, बहुकोणीय मुकाबले ने राजनीति बदली है। लिहाजा, आप, कांग्रेस, भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी— सभी के लिए अलग-अलग सियासी स्पेस बनते प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दिए थे। इन चुनावों से पंजाब में दो-दलीय राजनीति की बजाय बहुकोणीय राजनीति और मजबूत हुई है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

मानसिक वीर्य जो कि सृष्टि के इसलिए व्यास जी ने अपने अमोघवीर्यगत एक विशिष्ट कीटाणु को पूर्वप्रशित पद्धति के अनुसार परिपुष्ट करके पुत्ररूप में परिणत कर लिया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात हुई ?

घड़े से अगस्त्य और बसिष्ठ

कहा जाता है कि मित्रावरुण उर्वशी अप्सरा को देख कर क्षुब्ध हो गये, और अपना वीर्य यज्ञ कलश में डाल दिया, जिससे अगस्त्य और वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुवे। यह कथा न केवल असम्भव है बल्कि अश्लील भी है।

वैदिक स्वरूप

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्यां ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः।

द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वेदेवाः पुष्करे त्वा ददन्तः। 11।

अप्सरसः परिजज्ञे वसिष्ठः।।12।।

सत्रेजाता विषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम् ।

ततोहमानउदियाय मध्यात्ततो जातमृषिमाहुर्वसिष्ठम् । 13।

(ऋग्वेद 7 । 33)

अर्थात्- हे वशिष्ठ ! आप मित्रावरुण के पुत्र हो, हे ब्रह्मन्! उर्वशी को देख कर उक्त देवताओं का मानसिक द्रप्स (वीर्य) स्कन्न = (च्युत) हो गया था जिससे तुम उत्पन्न हुवे हो, इसलिये समस्त देवताओं ने दिव्य वेद-राशि सहित आपको पुष्कर में धारण किया था ।।11।। वसिष्ठ अप्सरा से उत्पन्न हुवे थे ॥ 12॥ यज्ञ में दीक्षित हुवे मित्र और वरुण ने दूसरों द्वारा प्रमाणित होने के बाद एक साथ ही कुम्भ (घड़े) में रेतः (वीर्य) को सींचा था, तब उस घट में से शमीप्रमाण अगस्त्य का प्रादुर्भाव हुआ था और उससे ही वसिष्ठ का जन्म हुवा था ।।13।।

क्रमशः ..

अद्रोहक कैसे बने दिव्य-द्रष्टा, जिनके जैसा जितेंद्रिय पुरुष कोई नहीं

आशुतोष गर्ग

पूर्वकाल में एक राजकुमार थे, जिनकी पत्नी रूप, गुण व शील में कामदेव की पत्नी रति व इंद्र की पत्नी शची के समान मन को मोहित करने वाली थी। उनका नाम भी सुंदरी था। राजकुमार अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन अचानक राजकुमार को किसी कार्य से दूर जाना पड़ा। उनके मन में चिंता थी। वह सोचने लगे, 'मैं अपनी पत्नी को कहां छोड़ूं, जहां इसका सतीत्व और सम्मान सुरक्षित रह सके?' बहुत विचार करने के बाद उन्हें एक व्यक्ति उपयुक्त लगा। वह थे, धर्मात्मा, जितेंद्रिय अद्रोहक।

राजकुमार, अद्रोहक के पास पहुंचे और उनसे अपनी पत्नी की रक्षा का निवेदन किया। अद्रोहक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, 'तात! मैं न आपका पिता हूं, न भाई, न कोई संबंधी। न ही मैं आपकी पत्नी के कुल का हूं। फिर आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं?'

राजकुमार बोले, 'महात्मन ! इस संसार में आपके समान धर्मपरायण और संयमी पुरुष दूसरा कोई नहीं है। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है।' अद्रोहक ने विनम्रता से कहा, 'ऐसी सुंदरी की रक्षा करना सरल नहीं है। नगर में अनेक कामी पुरुष हैं। यहां किसी स्त्री के सतीत्व की रक्षा करना बेहद कठिन है।' राजकुमार ने कहा, 'मैं सब सोच-विचार कर ही आपके पास आया हूं। जैसे भी हो, आप ही इसकी रक्षा करें।' फिर अद्रोहक ने कहा, 'यदि ये मेरे घर पर रहेंगी, तो इन्हें मेरी पत्नी के साथ मेरी शय्या पर ही सोना पड़ेगा, ताकि कोई संदेह न करे। परंतु मैं इनके साथ अनुचित व्यवहार करूंगा, तभी इनकी रक्षा कर पाना संभव है।' राजकुमार ने सोच-विचार करके कहा, 'मुझे स्वीकार है। आपको जो उचित लगे, वही कीजिए।' फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, 'सुंदरी, ये जो कुछ कहें, वही करना। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा।' यह कहकर राजकुमार चले गए।

अद्रोहक, प्रतिदिन अपनी पत्नी और सुंदरी के बीच में सोते थे। परंतु उनका मन विचलित नहीं हुआ। सुंदरी को वह माता के समान मानते थे। सुंदरी भी अद्रोहक को पिता के समान मानती थी। इस प्रकार दोनों संयमपूर्वक रहते थे। छह मास के बाद जब राजकुमार लौटे, तो उन्होंने लोगों से अपनी पत्नी और अद्रोहक के आचरण के विषय में पूछा। कुछ लोगों ने उनके निर्णय की प्रशंसा की, किंतु कुछ ने संदेहपूर्ण बातें भी कहीं। अद्रोहक ने लोगों की बातें सुनीं। उन्हें यह सोचकर दुख हुआ कि धर्मपूर्वक आचरण करने पर भी लोग उनके चरित्र को कलंकित कर रहे हैं। लोकनिंदा से मुक्त होने का संकल्प करके उन्होंने अपने लिए एक चिता बनाई और अग्नि प्रज्वलित की। उसी क्षण राजकुमार वहां पहुंच गए।

अद्रोहक ने उनसे कहा, 'मैंने आपके लिए कठोर धर्म निभाया, किंतु वह सब व्यर्थ हो गया। अब मैं आत्मदाह करूंगा।' इतना कहकर वह अग्नि में कूद पड़े।

देवताओं ने राजकुमार से कहा, 'इस संसार में अद्रोहक जैसा जितेंद्रिय पुरुष कोई नहीं है। इन्होंने काम, लोभ और क्रोध पर विजय पा ली है। इनके हृदय में भगवान श्रीवासुदेव निवास करते हैं। इनके दर्शन व स्पर्श से मनुष्य पापमुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है।' यह कहकर देवता स्वर्ग को लौट गए तथा राजकुमार अपनी पत्नी के साथ राजमहल। इस पुण्य-प्रभाव से अद्रोहक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई।

बालेन्द्र शाह ने सीमा विवाद सुलझाने जगहँसाई करवा ली

नीरज कुमार दुबे

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर चल रहा पुराना सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नया भू-राजनीतिक घटनाक्रम नहीं बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की चौंकाने वाली और कई मायनों में अपरिपक्व बयानबाजी बनी है। संसद में उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जिसने काठमांडू से लेकर नई दिल्ली तक हलचल मचा दी। हालात इतने असहज हो गए कि कुछ ही घंटों बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। और विडंबना देखिए, भारत को घेरने की कोशिश में दिया गया बयान नेपाल में ही प्रधानमंत्री के लिए भारी पड़ गया। विपक्ष, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व राजदूत और सीमा विशेषज्ञ तक उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनसे सबूत, स्पष्टीकरण, यहां तक कि माफी की मांग होने लगी। सीमा विवाद पर राजनीतिक परिपक्वता दिखाने के बजाय बालेन्द्र शाह की टिप्पणियां ऐसी साबित हुईं जिन्होंने नेपाल की आधिकारिक स्थिति को ही कठघरे में खड़ा कर दिया।

हम आपको बता दें कि नेपाली संसद में बोलते हुए बालेन्द्र शाह ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने दोनों देशों से तथ्यों का अध्ययन कर मित्रवत तरीके से विवाद सुलझाने की अपील की। उधर, नेपाल में विपक्षी दलों और पूर्व राजनयिकों ने बालेन्द्र शाह की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। नेपाली कांग्रेस की बसना थापा और अन्य नेताओं ने संसद के अभिलेखों से बयान हटाने की मांग की। पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कही। नेपाल के पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य और दीप कुमार उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय भूमि पर अतिक्रमण का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद

नहीं है। सीमा विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने भी प्रधानमंत्री की बातों को तथ्यात्मक आधार से रहित बताया। इस प्रकार बालेन्द्र शाह का बयान भारत से अधिक नेपाल के भीतर ही विवाद का विषय बन गया। दरअसल, सीमा विवाद का केंद्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र हैं। नेपाल का दावा है कि सुगौली संधि के अनुसार काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए उसके पूर्व का पूरा क्षेत्र नेपाली भूभाग है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम लिपुलेख दर्रे के नीचे स्थित स्रोतों से होता है और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कालापानी क्षेत्र लंबे समय से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा रहा है। यही मूल विवाद दोनों देशों के दावों की जड़ में है।

हम आपको बता दें कि विवाद को हाल में उस समय नया मोड़ मिला जब नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताते हुए भारत और चीन दोनों को कूटनीतिक नोट भेजा। भारत ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से लगातार संचालित हो रही है और यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है। भारत ने यह भी दोहराया कि एकतरफा तरीके से क्षेत्रीय दावों का विस्तार न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही स्वीकार्य है।

उधर, बालेन्द्र शाह के बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का आशय यह नहीं था कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। मंत्रालय के अनुसार सीमा के कुछ हिस्सों में सीमा स्तंभों की कमी, दशगजा क्षेत्र और सीमापार भूमि उपयोग जैसी व्यावहारिक समस्याओं के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जहां दोनों ओर के लोग एक-दूसरे की जमीन का उपयोग करते रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि दोनों देश कूटनीतिक बातचीत, तकनीकी सर्वेक्षण और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

लेकिन सबसे अधिक हैरानी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के उस सुझाव पर हुई जिसमें उन्होंने सीमा विवाद के समाधान में ब्रिटेन की भागीदारी की बात उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान सीमाओं की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल से जुड़ी है, इसलिए ब्रिटेन को भी इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। यह प्रस्ताव न केवल व्यावहारिक दृष्टि से कमजोर माना गया बल्कि नेपाल के भीतर भी इसे अपरिपक्व और अनावश्यक बताया गया। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हमेशा द्विपक्षीय ढांचे में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में तीसरे पक्ष को बीच में लाने की बात कूटनीतिक परंपराओं और स्थापित समझ से मेल नहीं खाती। इसके अलावा, सीमा विवाद जैसे संवेदनशील और पूर्णतः द्विपक्षीय विषय में ब्रिटेन को शामिल करने का सुझाव बालेन्द्र शाह की कूटनीतिक नासमझी का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन था जिसने कई जानकारों को हैरान कर दिया। भारत दशकों से स्पष्ट करता आया है कि वह अपने किसी भी द्विपक्षीय विवाद में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दखल को स्वीकार नहीं करता, चाहे मामला पाकिस्तान का हो, चीन का हो या नेपाल का। ऐसे में ब्रिटेन को बातचीत की मेज पर बुलाने का प्रस्ताव शुरू से ही अव्यावहारिक और वास्तविकताओं से कटा हुआ नजर आया। जिस देश ने दो शताब्दियों पहले उपमहाद्वीप छोड़ दिया, उसे आज की सीमा वार्ताओं में घसीटने की कोशिश को कई पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक अपरिपक्वता बताया। दिलचस्प यह है कि बालेन्द्र शाह की इस टिप्पणी पर केवल नेपाल में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के रणनीतिक और दक्षिण एशियाई मामलों पर नजर रखने वाले हलकों में भी हैरानी जताई गई और इसे अव्यावहारिक सोच का उदाहरण माना गया। कूटनीति की दुनिया में जहां गंभीरता, तैयारी और यथार्थवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है, वहां बालेन्द्र शाह का यह सुझाव कई लोगों को ऐसा लगा मानो किसी जटिल अंतरराष्ट्रीय विवाद के समाधान के लिए इतिहास की धूल झाड़कर ऐसे पात्रों को मंच पर बुलाने की कोशिश की जा रही हो जिनकी अब उस प्रक्रिया में कोई वास्तविक भूमिका ही नहीं बची है।

देखा जाये तो सामरिक दृष्टि से लिपुलेख क्षेत्र का महत्व अत्यंत गहरा है। यह भारत, नेपाल और चीन के त्रिसीमा क्षेत्र के निकट स्थित है। यह केवल धार्मिक यात्रा का मार्ग नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्र में संपर्क, निगरानी और रणनीतिक पहुंच का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। चीन की बढ़ती सक्रियता और हिमालयी क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच यह इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और भी संवेदनशील हो गया है। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़ा कोई भी राजनीतिक बयान केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके व्यापक सामरिक प्रभाव भी होते हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान इसी कारण अधिक विवादास्पद बन गया। बिना पर्याप्त तैयारी और तथ्यों की मजबूत प्रस्तुति के ऐसे संवेदनशील विषयों पर टिप्पणी करना न केवल कूटनीतिक भ्रम पैदा करता है बल्कि अपने ही देश की आधिकारिक स्थिति को कमजोर भी कर सकता है। यही कारण है कि उनकी टिप्पणियों के तुरंत बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा और देश के अनेक राजनीतिक तथा कूटनीतिक विशेषज्ञों ने उनकी आलोचना की। बहरहाल, यह पूरा प्रकरण एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े मतभेद अवश्य हैं, लेकिन दोनों देशों ने बार-बार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान की प्रतिबद्धता जताई है।

आज का इतिहास

1739 स्वीडन के स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की गई।
1763 पोंटियाक का विद्रोह: अब मैकिनो सिटी, मिशिगन, चिप्पवेस ने किले मिसिलिमैकिनैक पर कब्जा कर लिया, जो कि लारोंससे के एक खेल के साथ गैरीसन का ध्यान हटाने के बाद, किले में एक गेंद का पीछा किया था।
1771 आर्मिडा, एंटोनियो सालेरी द्वारा वियतना बर्गथेटर में एक ओपरेक ड्रामा प्रति संगीत प्रस्तुत किया।
1780 कैथोलिक विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लंदन में पार्लियामेंट पर हमला किया।
1793 फ्रांस में गिरांडिन का नाश हो गया।
1800 पहले चेचक का टीकाकरण उत्तर अमेरिका में ट्रिनिटी, न्यूफाउंडलैंड में किया गया।
1805 नेपोलियन के युद्धों - एक फ्रेंको-स्पेनिश बेड़े ने ब्रिटिश से फोर्ट-डी-फ्रांस की ओर जाने वाली खाड़ी के प्रवेश द्वार पर एक निर्जन द्वीप डायमंड रॉक को फिर से कब्जा कर लिया।
1848 पान-स्लाववाद आंदोलन के भाग के रूप में, प्राग में प्राग स्लाव कांग्रेसबेगन, कई बार पहली बार जब यूरोप के सभी स्लावोपुलेशन से आवाज़ें एक ही स्थान पर सुनी गईं।
1851 अमेरिका में पहली बार मैन प्रांत में मद्यपान निषेध कानून लागू किया गया।
1866 फेनियन छापे-द रिडवे की लड़ाई, कनाडाई सैनिकों द्वारा विशेष रूप से नेतृत्व करने और कनाडाई अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नेतृत्व करने के लिए ओन्टारियो में पहला स्थान।
1868 पहला ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आयोजित किया गया।
1886 ग्रोवर क्लीवलैंड व्हाइट हाउस में शादी करने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति बने जब उन्होंने फ्रांसेस फोलसम को विवाहित किया।
1896 जी मार्कोनी ने रेडियो को अपने नाम पर पेटेंट कराने के लिये आवेदन दिया जो बाद में दो जुलाई 1897 को स्वीकार कर लिया गया।
1901 कत्सुरा तारो जापान के प्रधानमंत्री बने।
1902 एन्थ्रेसाइट कोयले की हड़ताल अमेरिका में शुरू हुई।
1909 एलफ्रेड डेकिन लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए।
1910 रोल्स-रॉयस के सह-संस्थापक चार्ल्स रोल्स इंग्लिश चैनल बायप्लेन के एक गैर-स्टॉप डबल क्रॉसिंग बनाने वाले पहले व्यक्ति बन गए।

मुश्किल में है आधी आबादी की आवाजाही

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत में किसी बस स्टॉप पर खड़ी स्त्री का दृश्य सामान्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि हम उसे थोड़ा गहराई से देखें तो वह केवल एक यात्री नहीं दिखाई देती। वह अपने साथ समाज की अनेक परतें, संघर्ष, उम्मीदें और सवाल लेकर खड़ी होती है। वह बस का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन साथ ही वह अपने अधिकारों, अवसरों और सम्मानजनक अस्तित्व की भी प्रतीक्षा कर रही होती है। विडंबना यह है कि जिस दृश्य को हम प्रतिदिन देखते हैं, उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों को समझने की कोशिश बहुत कम करते हैं।

भारतीय समाज में पुरुष और महिला की सार्वजनिक उपस्थिति को लेकर आज भी एक बड़ा अंतर मौजूद है। यदि रात के समय कोई पुरुष सड़क पर चलता हुआ दिखाई दे, बस का इंतजार करता मिले या किसी चाय की दुकान पर बैठा हो, तो यह एक सामान्य बात मानी जाती है। लेकिन यदि वही दृश्य किसी महिला के साथ हो तो अनेक प्रश्न स्वत: खड़े हो जाते हैं। वह कहाँ जा रही है? अकेली क्यों है? इतनी देर तक बाहर रहने की क्या आवश्यकता है? कौन उसका इंतजार कर रहा होगा? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं हैं, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता के प्रतीक हैं जो महिलाओं की स्वतंत्र आवाजाही को अब भी पूरी तरह सहजता से स्वीकार नहीं कर पाई है।

यह स्थिति केवल छोटे शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। महानगरों में भी महिलाएँ सार्वजनिक स्थानों पर स्वयं को पुरुषों की तुलना में अधिक असुरक्षित महसूस करती हैं। उनके लिए घर से बाहर निकलना केवल एक भौतिक यात्रा नहीं होता, बल्कि अनेक मानसिक और सामाजिक बाधाओं को पार करने की प्रक्रिया भी होता है। इसीलिए महिलाओं की आवाजाही से जुड़ी योजनाओं, सुविधाओं और नीतियों का महत्व केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी होता है।

जब सरकारें महिलाओं के लिए मुफ्त या रियायती बस यात्रा जैसी योजनाएँ लागू करती हैं, तो उसका महत्व केवल किराए की बचत तक सीमित नहीं रहता। यह उन महिलाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलता है जिनके लिए प्रतिदिन का छोटा-सा खर्च भी निर्णयों को प्रभावित करता है। कई परिवारों में आज भी महिलाओं की शिक्षा, नौकरी या अन्य गतिविधियों पर होने वाला खर्च एक अतिरिक्त बोझ माना जाता है। ऐसे में परिवहन का खर्च कम होना उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है।

यह समझना आवश्यक है कि घर से बाहर निकलने वाली हर महिला केवल नौकरी पर नहीं जा रही होती। वह अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर बढ़ रही हो सकती है। कोई महिला अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए दूसरे मोहल्ले या शहर जा रही हो सकती है। कोई विवाह के बाद छूट गई पढ़ाई को फिर से शुरू करने का साहस जुटा रही हो सकती है। कोई बेहतर रोजगार की तलाश में प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर रही हो सकती है। कोई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अतिरिक्त काम कर रही हो सकती है। और यह भी संभव है कि वह केवल कुछ क्षणों की मानसिक शांति के लिए घर से बाहर निकली हो, क्योंकि घर के भीतर उसका अवैतनिक श्रम कभी समाप्त नहीं होता।

भारतीय समाज में महिलाओं का घरेलू श्रम आज भी बड़े पैमाने पर अदृश्य बना हुआ है। भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की सेवा करना, घर की साफ-सफाई और अनगिनत छोटे-बड़े काम—ये सब ऐसे कार्य हैं जिनके बिना परिवार का जीवन संभव नहीं है, लेकिन इनका आर्थिक मूल्य नहीं आँका जाता। ऐसे में जब कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो वह केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि अनेक जिम्मेदारियों के बोझ के साथ निकलती है। उसके पास समय कम होता है, संसाधन सीमित होते हैं और सामाजिक अपेक्षाएँ अधिक होती हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति को लेकर हमारी सामाजिक सोच में भी अनेक विरोधाभास दिखाई देते हैं। एक ओर हम महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, दूसरी ओर उनकी स्वतंत्र आवाजाही को लेकर संदेह और नियंत्रण की प्रवृत्ति भी बनाए रखते हैं। परिवार अक्सर बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन देर शाम घर लौटने को लेकर चिंतित रहते हैं। वे चाहते हैं कि महिलाएँ आगे बढ़ें, लेकिन उनके रास्ते में अनेक सामाजिक सीमाएँ भी खड़ी कर देते हैं।महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन केवल यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक भागीदारी का माध्यम भी है। यदि परिवहन सुलभ, सुरक्षित और किफायती हो तो महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। दुनिया भर के अनेक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि महिलाओं की गतिशीलता बढ़ने से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए महिलाओं की आवाजाही को केवल परिवहन नीति के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक विकास की नीति के रूप में देखा जाना चाहिए।

सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में महिलाओं की बड़ी संख्या आज भी इसलिए अवसरों से वंचित रह जाती है क्योंकि उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध नहीं होता। अनेक छात्राएँ दूर के कॉलेजों में प्रवेश नहीं लेतीं क्योंकि यात्रा कठिन या असुरक्षित होती है। कई महिलाएँ बेहतर नौकरी के अवसर छोड़ देती हैं क्योंकि देर शाम लौटना उनके लिए जोखिमपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार असुरक्षित सार्वजनिक स्थान केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही सीमित नहीं करते, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को भी प्रभावित करते हैं।

हालाँकि केवल सुरक्षा की चर्चा पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर सम्मानजनक व्यवहार भी उतना ही आवश्यक है। महिलाओं को अक्सर घूरती निगाहों, अनावश्यक टिप्पणियों और असहज वातावरण का सामना करना पड़ता है। यह अनुभव उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है और कई बार उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के लिए मजबूर करता है। किसी भी सभ्य समाज की पहचान केवल अपराध दर से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वहाँ लोग एक-दूसरे के प्रति कितना सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं।यह भी ध्यान देने योग्य है कि सार्वजनिक अनुशासन का प्रश्न केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। फुटपाथों पर अवैध पार्किंग, यातायात नियमों की अवहेलना, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाना और सामुदायिक संसाधनों का दुरुपयोग जैसी समस्याओं में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी दिखाई देती है। इसलिए समाधान भी सामूहिक होना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान रूप से नागरिक जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। सार्वजनिक जीवन तभी बेहतर बन सकता है जब अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी महत्व दिया जाए।शहरों की संरचना और विकास योजनाओं में भी महिलाओं की आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। अधिकांश शहर पुरुष-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विकसित हुए हैं। सड़कें, परिवहन प्रणाली, सार्वजनिक शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाएँ अक्सर महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गईं।

क्या गुंडागर्दी ही अब नई राजनीति है?

दिलीप कुमार पाठक

पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला बेहद परेशान करने वाला है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती, फिर चाहे वह किसी भी नेता या दल के खिलाफ क्यों न हो। मतभेद अपनी जगह हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब बात मारपीट, कपड़े फाड़ने और जानलेवा हमलों तक पहुंच जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा समाज और हमारी राजनीति बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी सभ्य समाज में ऐसी हरकतों को सही नहीं ठहराया जा सकता। बंगाल को हमेशा से एक बेहद खास राज्य माना गया है। यह रवींद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। इस मिट्टी से हमेशा ज्ञान, कला, संस्कृति और बड़े-बड़े विचारों की खुशबू आती रही है। बंगाल के लोग अपनी तेज बुद्धि और वैचारिक बहस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज उसी बंगाल से जब रोज-रोज राजनीतिक हिंसा, मारपीट और बमबाजी की खबरें आती हैं, तो दिल दहल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी पहचान कहीं खो गई है और उसकी जगह सिर्फ सत्ता की भूख ने ले ली है। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जिस धरती को देश का मार्गदर्शक होना चाहिए था, वह आज राजनीतिक रंजिश का अखाड़ा बन चुकी है? आज की राजनीति में एक अजीब सा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव आते-जाते रहते हैं, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे हर कोई अपनी पुरानी निष्ठाएं बदलकर सत्ताधारी खेमे में शामिल होना चाहता है। दल-बदल और विचारधाराओं का यह खेल सिर्फ कुर्सी के लिए हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ, जब हम तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का रवैया देखते हैं, तो गंभीर सवाल उठते हैं। एक राजनीतिक दल का काम जनता की सेवा करना और अपनी नीतियों से उनका दिल जीतना होता है। लेकिन जब कोई दल अपने विरोधियों को डराने-धमकाने लगे, हर बात का जवाब लाठी और पत्थरों से देने लगे, तो जनता के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह कोई राजनीतिक संगठन है या फिर भय फैलाने वाला कोई गिरोह?

लोकतंत्र में किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है।इस हमले के बाद हमेशा की तरह राजनीति भी शुरू हो गई है। टीएमसी इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता का गुस्सा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस और अन्य दलों के बड़े नेताओं ने भी इस घटना का विरोध किया है। सच तो यह है कि जब नेता और पार्टियां एक-दूसरे को सिर्फ राजनीतिक विरोधी न मानकर जानी दुश्मन समझने लगते हैं, तो ऐसी ही हिंसक तस्वीरें सामने आती हैं। नफरत की यह राजनीति हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिसाल बन रही है। अगर आज बंगाल में इस तरह की हिंसा को सामान्य मान लिया गया, तो कल को पूरे देश में यही तरीका अपना लिया जाएगा। हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र की असली ताकत उसकी विविधता और शांतिपूर्ण चर्चाओं में है। लाठी-डंडों से किसी की आवाज को दबाया तो जा सकता है, लेकिन किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि इंसानियत ही खत्म हो जाए। चाहे हमला करने वाले किसी भी दल के हों, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए ताकि कानून का डर बना रहे। सभी दल और आम जनता मिलकर इस बात पर विचार करें कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने और सत्ता हथियाने का जरिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका असली मकसद देश और समाज का भला करना होना चाहिए। लोकतंत्र तभी बचेगा जब हम एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखेंगे।

ट्रंप की चीन यात्रा के राजनीतिक मायने ज्यादा

राजीव रंजन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान राजशाही जमाने के बगीचे 'चोंगनानहाय' में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप की चहलकदमी भले ही एक औपचारिक दृश्य लगे, परंतु चीन की नजर में इसका मतलब कहीं गहरा था। यह एक कूटनीतिक कदम था, ताकि उस रिश्ते को फिर से पटरी पर लाया जा सके, जो दशकों से राजनीतिक उलझन और सामरिक तनाव में रहा है। चोंगनानहाय परिसर में शी द्वारा ट्रंप की अगवानी करना एक राजनयिक संकेत है कि बीजिंग वाशिंगटन से अपने रिश्तों को लेकर गंभीर है, वहीं यह ट्रंप के अहम को साधने का सटीक बाण भी था।

यह दौरा न केवल प्रतीकात्मक था, बल्कि वर्षों के टकराव के बाद दोनों महाशक्तियों का आर्थिक वास्तविकताओं के आगे नतमस्तक होना भी था। इसने स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की भूमिका को न तो नकारा जा सकता है, न ही उससे आसानी से पल्ला झाड़ा जा सकता है। नौ वर्ष में पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति बीजिंग गया था। सो, चीन के लिए यह एक कूटनीतिक दौरा भर नहीं था, बल्कि वह अपने द्विध्रुवीय दुनिया की सोच पर अमेरिकी मुहर लगा रहा था। इस यात्रा का सबसे दिलचस्प पहलू था ट्रंप के साथ आया कारोबारी दल, जिसमें सत्रह बड़े सीइओ शामिल थे।

एलन मस्क, टिम कुक, जेंसन हुआंग, बोइंग के प्रमुख और ब्लैकरॉक तथा गोल्डमैन सैक्स के दिग्गजों की मौजूदगी चीन की अहमियत खुद बता रही थी। अमेरिका को तेल, गैस, सोयाबीन, मकई, हवाई जहाज और वित्तीय सेवाओं के बड़े सौदे चाहिए थे। बोइंग को चीन से अपने विमानों के ऑर्डर चाहिए थे, कृषि कंपनियों को नये समझौते, और चिप कंपनियां तकनीक हस्तांतरण पर छूट की उम्मीद में थीं। चीन ने इन कारोबारियों का गर्मजोशी से स्वागत कर साफ संदेश दिया कि चीनी दरवाजे खुले हैं और 1.4 अरब लोगों के इस बाजार और विनिर्माण क्षमता को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं।

वास्तव में ट्रंप की इस यात्रा ने दिखाया कि दोनों देशों

की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे पर कितनी निर्भर हैं। अमेरिकी कंपनियां चीन की उत्पादन क्षमता और विशाल उपभोक्ता आधार के बिना अपनी वैश्विक वृद्धि की कल्पना भी नहीं कर सकतीं। उधर चीन भी अमेरिकी प्रौद्योगिकी, निवेश और बाजार से लाभान्वित होता रहा है। दोनों देशों के बीच तनातनी से अमेरिकी किसानों के सोयाबीन निर्यात में भारी कमी आयी थी, जबकि चीनी कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला में अड़चन। इस पृष्ठभूमि में ट्रंप का यह दौरा व्यावहारिक जरूरतों का परिणाम लगता है। यात्रा के दौरान अनौपचारिक बातचीत के लिए जो जगहें चुनी गयीं, वे भी कई संकेत दे रही थीं।

पीपुल्स ग्रेट हॉल में औपचारिक बैठक तो रस्म के मुताबिक थी, पर मिंग राजवंश के 600 साल पुराने स्वर्ग मंदिर इमारत की 'गोल स्वर्ग, चौकोर पृथ्वी' दार्शनिकता के माध्यम से शी ने ट्रंप को चीनी सभ्यता और शासन पद्धति का बड़प्पन दिखाया। जब ट्रंप ने चीन को बेहद खूबसूरत कहा, तो उसे चीनी मीडिया ने चीनी संस्कृति और विकास मॉडल की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता से जोड़कर देखा। यह सांस्कृतिक प्रदर्शन चीन की प्राचीन सभ्यता की निरंतरता और उसके वर्तमान वैश्विक महत्व को रेखांकित करने का तरीका था। शी ने बातचीत के दौरान तीन सवाल उठाये। पहला, क्या दोनों देश 'थ्यूसीडाइड्स ट्रैप' से बच सकते हैं, यानी क्या दो बड़ी ताकतें बिना लड़े साथ रह सकती हैं। दूसरा, क्या वे जलवायु बदलाव और दुनिया के दूसरे संकटों पर मिलकर काम कर सकते हैं। तीसरा, क्या दोनों देश अपने लोगों और पूरी मानवता की भलाई को प्राथमिकता दे सकते हैं। इन प्रश्नों के जरिये शी जिनपिंग को वैश्विक दक्षिण की नजर में एक जिम्मेदार और दूरदर्शी नेता के रूप में पदस्थापित करने की चीनी सोच सामने आयी।

पूरी यात्रा में ट्रंप काफी संयमित और गंभीर दिखे। उन्होंने शी को पुराना दोस्त कहा और रिश्ते की अहमियत की तारीफ की। इसके पीछे कई वजहें थीं। देश में मध्यावधि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं और 2025 के व्यापार आंकड़ों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरियां उजागर कर दी हैं। एक अनुभवी व्यवसायी की तरह ट्रंप समझ गये हैं कि लंबा टकराव अमेरिका के लिए भी महंगा सौदा है। इस दौरान शी ने अमेरिका-चीन संबंधों के लिए पुन: एक नया ढांचा 'रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता' सामने रखा। मतलब यह कि प्रतिस्पर्धा हो, पर नियंत्रित और टकराव से बचा जाये। पर प्रश्न यह है कि 'महाशक्तिशाली देशों के लिए नये प्रकार के संबंध' की जो चीनी अवधारणा थी, उसकी भांति अमेरिका इस अवधारणा को भी तवज्जो न दे तो।

क्योंकि चीन अब अपनी अवधारणा, मानक और आदर्शों को बड़े सलीके से वैश्विक शासन प्रतिमान में ढाल रहा है। दूसरी ओर ताइवान, तकनीक और टैरिफ पर अमेरिका और चीन में गहरे मतभेद अभी भी बने हुए हैं। ट्रंप की चीन यात्रा ने साबित किया कि आर्थिक हकीकतें राजनयिक बयानबाजी से ज्यादा असरदार और प्रभावी हैं। हालांकि, ट्रंप के अप्रत्याशित व्यवहार और नीतियों को देखते हुए, अमेरिका-चीन संबंधों में आमूलचूल सकारात्मक बदलाव आयेगा, यह सोचना बेमानी होगा, पर एक ठहराव की गुंजाइश दिख तो रही है।

क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक के कूटनीतिक मायने

कमलेश पांडे

भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति-संतुलन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरी है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो-पैसिफिक, समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, ऊर्जा और चीन की बढ़ती आक्रामकता जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाई।

देखा जाए तो नई दिल्ली की यह बहुप्रतीक्षित क्वाड बैठक यह बताती है कि आने वाले दशक में वैश्विक राजनीति का केंद्र यूरोप से हटकर इंडो-पैसिफिक बनने जा रहा है, और इस नई भू-राजनीतिक व्यवस्था में भारत केवल सहभागी नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसका सारा श्रेय मोदी प्रशासन और आरएसएस के प्रति समर्पित बुद्धिजीवियों को जाता है, जिन्होंने अपनी सधी हुई रणनीति का वैश्विक कमाल दिखा दिया। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड क्या है? तो यह जान लीजिए कि Quadrilateral Security Dialogue यानी Quad चार लोकतांत्रिक देशों- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया- का रणनीतिक समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक को सुरक्षित रखना है।

क्वाड देशों के विदेशमंत्रियों की नई दिल्ली बैठक से निकले राष्ट्रीय मायने निम्नलिखित हैं - पहला, भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत: दिल्ली में बैठक आयोजित होना यह दिखाता है कि इंडिया अब इंडो-पैसिफिक राजनीति का केंद्रीय खिलाड़ी बन चुका है। भारत, अमेरिका और पश्चिम के लिए संतुलित साझेदार है। वैश्विक दक्षिण और पश्चिमी शक्तियों के बीच सेतु की भूमिका निभा रहा है। चीन के मुकाबले लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में उभर रहा है।

दूसरा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लाभ: क्वाड की समुद्री निगरानी पहल भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हिंद महासागर में भारतीय

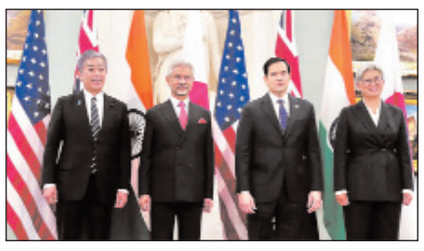

निगरानी क्षमता बढ़ेगी। चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी। भारतीय नौसेना को तकनीकी सहयोग मिलेगा।

तीसरा, आर्थिक और तकनीकी अवसर: क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा सहयोग से भारत को: नई निवेश संभावनाएँ, सप्लाई चेन हब बनने का मौका, मैन्युफैक्चरिंग विस्तार, और हाई-टेक उद्योगों में बढ़त मिल सकती है। चौथा, आतंकवाद पर भारत की चिंता को समर्थन: बैठक में आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद की निंदा की गई, जिसमें पहलगाम हमले का भी उल्लेख हुआ। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक समर्थन है, विशेषकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर, और वैश्विक मंचों पर भारत की सुरक्षा चिंताओं को वैधता देने में।

पांचवां, भारत-अमेरिका संबंधों में नई ऊर्जा: हाल के समय में टैरिफ और रणनीतिक मतभेदों के बावजूद बैठक ने दिखाया कि क्वाड ढांचा अभी भी मजबूत है। इससे संकेत मिलता है कि भारत और अमेरिका दोनों चीन को लेकर दीर्घकालिक सहयोग चाहते हैं। क्वाड व्यक्तिगत नेताओं से ऊपर उठकर संस्थागत रूप ले रहा है। वहीं, क्वाड देशों के विदेशमंत्रियों की हालिया हुई बैठक के अंतरराष्ट्रीय मायने निम्नलिखित हैं- पहला, चीन को सामरिक संदेश: बैठक का सबसे बड़ा संकेत चीन के लिए था। संयुक्त बयान में दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में बलपूर्वक यथास्थिति बदलने पर चिंता जताई गई। इसका अर्थ हुआ कि चीन की समुद्री सैन्य गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी। इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश तेज होगी। क्वाड अब केवल संवाद मंच नहीं बल्कि रणनीतिक समन्वय मंच बनता दिख रहा है।

दूसरा, इंडो-पैसिफिक में नई भू-राजनीतिक धुरी: क्वाड देशों ने समुद्री निगरानी, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सुरक्षा पर नई पहलें शुरू कीं। फिजी में संयुक्त पोर्ट परियोजना इसकी मिसाल है। इससे प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन का प्रभाव संतुलित करने की कोशिश होगी। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक नई रणनीतिक कनेक्टिविटी बनेगी। छोटे देशों को चीनी कर्ज कूटनीति का विकल्प मिलेगा।

तीसरा, सप्लाई चेन और क्रिटिकल मिनरल्स की राजनीति क्वाड ने क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा पर नया फ्रेमवर्क बनाया। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि: चीन रेयर अर्थ मिनरल्स में वैश्विक प्रभुत्व रखता है। सेमीकंडक्टर, रक्षा और ढ्ढ उद्योग इन खनिजों पर निर्भर हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर चीन-निर्भरता कम करना चाहते हैं। चौथा, पश्चिम एशिया संकट और समुद्री व्यापार: बैठक में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी की सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई। इसके मायने ये हुए कि ईरान-इजरायल तनाव का असर वैश्विक व्यापार पर पड़ रहा है। क्वाड वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। ऊर्जा आपूर्ति और तेल कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश है।

पांचवां, एशियाई नैटो की बहस तेज: चीन लगातार क्वाड को ब्लॉक राजनीति कहता रहा है। हालांकि क्वाड खुद को नैटो नहीं मानता, लेकिन सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। समुद्री निगरानी और तकनीकी साझेदारी गहरी हो रही है। साझा सुरक्षा सोच विकसित हो रही है।

सच कहूं तो नई दिल्ली की यह क्वाड बैठक बताती है कि आने वाले दशक में वैश्विक राजनीति का केंद्र यूरोप से हटकर इंडो-पैसिफिक बनने जा रहा है। और इस नई भू-राजनीतिक व्यवस्था में भारत केवल सहभागी नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

कांग्रेस के लिए सिद्धारमैया को नजरअंदाज करना मुश्किल

राहिल नोरा चोपड़ा

सिद्धारमैया, जो कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ने इस्तीफा दे दिया और अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी डी.के. शिवकुमार के लिए रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि, कांग्रेस आलाकमान को पार्टी के भीतर सिद्धारमैया के वफादारों को विश्वास में लेना होगा। इसमें उन्हें कैबिनेट में जगह देना और राज्य कांग्रेस इकाई में नेतृत्व के पद प्रदान करना शामिल हो सकता है। सिद्धारमैया एक जमीनी स्तर के नेता हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण स्थानीय समर्थन प्राप्त है। ओ.बी.सी. के बीच उनके समर्थन आधार को नजरअंदाज करना मुश्किल है। पिछले 2 दशकों में कांग्रेस में आने के बाद से, सिद्धारमैया कांग्रेस के 'अहिंदा' सामाजिक गठबंधन के वास्तुकारों में से एक रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों को एक साथ लाए और कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी गणित को आकार देने में सहायक रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें राज्यसभा सीट की पेशकश की और उन्हें एक राष्ट्रीय भूमिका दी थी। यह कदम एक तीर से दो निशाने साधने जैसा था। पहला, राहुल गांधी के सामाजिक न्याय अभियान को बढ़ावा देने के लिए सिद्धारमैया जैसे ओ.बी.सी. नेता को राष्ट्रीय स्तर पर लाना। दूसरा, सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच टकराव को चतुराई से टालना। लेकिन सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव को लेने से इंकार कर दिया और घोषणा की कि वह राज्य में सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे और अपनी अंतिम सांस तक सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लडने की कसम खाई। निकट भविष्य में चाहे कुछ भी हो, सिद्धारमैया 2028 में कांग्रेस की फिर से चुनाव जीतने की कोशिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। राहुल-धर्मेंद्र प्रधान के बीच जुबानी जंग : सी.बी.एस.ई. ऑन-स्क्रीन मार्किंग विवाद को लेकर राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच जुबानी जंग जारी रही और इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सी.बी.एस.ई. परीक्षा और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओ.एस.एम.) मुद्दे पर अपनी टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ा जवाब दिया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनावी हार के कारण निराश दिख रहे हैं और भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ नहीं खड़े हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विवाद के कारण छात्र अतिरिक्त तनाव का सामना न करें। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सी.बी.एस.ई. परिणाम को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परवाह होती, तो उन्होंने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया होता। सी.बी.एस.ई. ओ.एस.एम. मुद्दे पर अपने सवालों को दोहराते हुए, गांधी ने पूछा कि सी.ओ.ई.एम.पी.टी. को अनुबंध क्यों दिया गया, जबकि कंपनी पहले भी किसी अन्य नाम से विवादों में रही थी। भाजपा के नए राज्य पार्टी प्रमुख : भाजपा ने तीन राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए नए राज्य इकाई अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की, जिनमें त्रिपुरा, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं। ये नियुक्तियां ऐसे समय में हुई हैं, जब भाजपा विभिन्न राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी समीकरणों वाले राज्यों में पार्टी के राज्य नेतृत्व ढांचे को मजबूत करने और अपनी संगठनात्मक मशीनरी को तेज करने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। हर्ष मल्होत्रा को भाजपा की दिल्ली इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि केवल सिंह ढिल्लों पंजाब में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। हरियाणा में पार्टी ने डा. अर्चना गुप्ता को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को भाजपा की त्रिपुरा राज्य इकाई का अध्यक्ष नामित किया गया है। इस बीच, दिल्ली भाजपा के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बनी हुई है, क्योंकि हाल के चुनावी मुकाबलों ने केसरिया पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया है, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने यह प्रमुख निर्णय पंजाब में एक सिख चेहरा पेश करने की रणनीतिक चाल के हिस्से के रूप में लिया है, जिसमें 2027 के विधानसभा चुनावों पर जोर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे : पश्चिम बंगाल विधानसभा में हालिया चुनावी हार ने तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) में एक डोमिनो प्रभाव पैदा कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नए इस्तीफे हुए हैं। हालिया हाई-प्रोफाइल इस्तीफा पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन का है, जिन्होंने टी.एम.सी. के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अपने संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है, जबकि टी.एम.सी. पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने पार्टी प्रवक्ता पद छोड़ दिया और कोलकाता नगर निगम की लोक लेखा समिति में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

स्पंदन राधा कृष्ण का

राधा का अर्थ है ...मोक्ष की प्राप्ति। रा का अर्थ है मोक्ष और ध का अर्थ है प्राप्ति। कृष्ण जब वृन्दावन से मथुरा गए, तब से उनके जीवन में एक पल भी विश्राम नही था। उन्होंने आततायियों से प्रजा की रक्षा की, राजाओं को उनके लुटे हुए राज्य वापिस दिलवाए और सोलह हज़ार स्त्रियों को उनके स्त्रीत्व की गरिमा प्रदान की। उन्होंने अन्य कईं जनहित कार्यों में अपने जीवन का उत्सर्ग किया।

राधा का अर्थ है ...मोक्ष की प्राप्ति। रा का अर्थ है मोक्ष और ध का अर्थ है प्राप्ति। कृष्ण जब वृन्दावन से मथुरा गए, तब से उनके जीवन में एक पल भी विश्राम नही था। उन्होंने आततायियों से प्रजा की रक्षा की, राजाओं को उनके लुटे हुए राज्य वापिस दिलवाए और सोलह हज़ार स्त्रियों को उनके स्त्रीत्व की गरिमा प्रदान की। उन्होंने अन्य कईं जनहित कार्यों में अपने जीवन का उत्सर्ग किया। श्रीकृष्ण ने किसी चमत्कार से लड़ाइयाँ नहीं जीती। बल्कि अपनी बुद्धि योग और ज्ञान के आधार पर जीवन को सार्थक किया। मनुष्य का जन्म लेकर , मानवता की...उसके अधिकारों की सदैव रक्षा की। वे जीवन भर चलते रहे , कभी भी स्थिर नही रहे । जहाँ उनकी पुकार हुई,वे सहायता जुटाते रहे। उधर जब से कृष्ण वृन्दावन से गए, गोपियाँ और राधा तो मानो अपना अस्तित्व ही खो चुकी थी। राधा ने कृष्ण के वियोग में अपनी सुधबुध ही खो दी। मानो उनके प्राण ही न हो केवल काया मात्र रह गई थी। राधा को वियोगिनी देख कर ,कितने ही महान कवियों- लेखकों ने राधा के पक्ष में कान्हा को निर्मोही जैसी उपाधि दी। दे भी क्यूँ न ?

राधा का प्रेम ही ऐसा अलौकिक था...उसकी साक्षी थी यमुना जी की लहरें, वृन्दावन की वे कुंजन गलियाँ , वो कदम्ब का पेड़, वो गोधुली बेला जब श्याम गायें चरा कर वापिस आते थे , वो मुरली की स्वर लहरी जो सदैव वहाँ की हवाओं में विद्यमान रहती थी। राधा जो वनों में भटकती ,कृष्ण कृष्ण पुकारती,अपने प्रेम को अमर बनाती,उसकी पुकार सुन कर भी ,कृष्ण ने एक बार भी पलट कर पीछे नही देखा। ...तो क्यूँ न वो निर्मोही एवं कठोर हृदय कहलाए। राधा का प्रेम ही ऐसा अलौकिक था...उसकी साक्षी थी यमुना जी की लहरें , वृन्दावन की वे कुंजन गलियाँ , वो कदम्ब का पेड़, वो गोधुली बेला जब श्याम गायें चरा कर वापिस आते थे , वो मुरली की स्वर लहरी जो सदैव वहाँ की हवाओं में विद्यमान रहती थी ... किन्तु कृष्ण के हृदय का स्पंदन किसी ने नहीं सुना। स्वयं कृष्ण को कहाँ कभी समय मिला कि वो अपने हृदय की बात..मन की बात सुन सकें। या फिर क्या यह उनका अभिनय था? जब अपने ही कुटुंब से व्यथित हो कर वे प्रभास -क्षेत्र में लेट कर चिंतन कर रहे थे तब जरा के छोडे तीर की चुभन महसूस हुई। तभी उन्होंने देहोत्सर्ग करते हुए, राधा शब्द का उच्चारण किया। जिसे जरा ने सुना और उद्धव को जो उसी समय वह पहुँचे..उन्हें सुनाया। उद्धव की आँखों से आँसू लगतार बहने लगे। सभी लोगों को कृष्ण का संदेश देने के बाद ,जब उद्धव ,राधा के पास पहुँचे ,तो वे केवल इतना कह सके -

राधा, कान्हा तो सारे संसार के थे,
किन्तु राधा तो केवल कृष्ण के हृदय में थी

कष्टहरता जय हनुमान...

हनुमान बजरंगबली और महावीर के नामों से जाने जाने वाले पवनसुत सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। पद्म-पुराण के 56-6-7 वें श्लोक में उनका अन्य छः चिरंजीवियों के साथ नाम इस प्रकार आता है-

अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानन्च विभीषण।
कृप परशुरामश्च सप्तैत चिरंजीविन ।

वस्तुतः रामभक्त, संकटमोचन, रामसेवक, रामदूत, केशरीनंदन, आंजनेय, अंजनीसुत, कपीश, कपिराज, पवनसुत और संकटमोचक के रूप में विख्यात हनुमान अपने भक्तों को व्याधियों व संकटों, वेदनाओं तथा परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं।

हनुमान भक्ति व पूजा का लाभ

हर व्यक्ति को जीवन में अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है, ऐसे में हनुमानजी का स्मरण उसकी कष्टों से रक्षा करता है। जहाँ हनुमानजी का नाम मुश्किलों से बचाव करता है, वहीं वह मन से अनजाने भय को निकालकर शुभ व मंगल का पथ प्रशस्त करता है, विपत्तियों से मुक्ति दिलाता है।

वास्तव में, हनुमानजी रामभक्ति, सत्य मर्यादा, ब्रह्मचर्य, सदाचार व त्याग की चरम सीमा हैं। इसका सविस्तार वर्णन हमें सुंदरकांड में मिलता है। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ करने से अनिष्ट, अमंगल तथा संकट की समाप्ति होती है, और नेष्ट का रास्ता खुलता है। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमानजी प्रसन्न होते हैं, तथा भक्त को सुपरिणाम प्रदान करते हैं।

कार्यसिद्धि के लिए भी सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। परंतु इस हेतु पाठ अमावस्या की रात्रि से शुरू करके नियमित रूप से 45 दिन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नवरात्रि के समय भी सुंदरकांड का पाठ करना उचित माना जाता है। एक ऐसी भी मान्यता है कि नौ ग्रहों को रावण की कैद से केशरीनंदन ने ही मुक्त कराया था। उस समय शनि ने हनुमानजी को वचन दिया था कि- हे हनुमान! जो कोई भी आपकी पूजा-अर्चना करेगा, मैं उसे नहीं सताऊँगा। साधक को मंगलवार व शनिवार की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यथार्थ तो यह है कि कलियुग में महावीर हनुमान का नाम सही अर्थों में संकटमोचन है।

माँ गंगा का प्राकट्य

शिव का हिमालय और गंगा से घनिष्ठ संबंध है और गंगा से उनके संबंध की कथा से लोकप्रिय चित्रांकन बड़ा समृद्ध हुआ है। हिंदुओं के लिए समस्त जल, चाहे वह सागर हो या नदी, झील या वर्षाजल, जीवन का प्रतीक है और उसकी प्रकृति दैवी मानी जाती है। इस संदर्भ में प्रमुख हैं तीन पवित्र नदियाँ- गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती। इनमें से पहली नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

चूँकि गंगा स्त्रीलिंग हैं, इसलिए उसे लंबे केशों वाली महिला के रूप में अंकित किया जाता है। देवी के रूप में गंगा उन सबके पाप धो देती है जो इतने भाग्यशाली हों कि उनकी भस्म उसके पवित्र जल में प्रवाहित की जाए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गंगा को संबोधित करने वाले एक पद में स्वयं शिव कहते हैं- पृथ्वी पर लाखों जन्म-जन्मान्तर के दौरान एक पापी जो पाप के पहाड़ जुटा लेता है, गंगा के एक पवित्र स्पर्श मात्र से लुप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस पवित्र जल से आर्द्र हवा में साँस भी ले लेगा, वह निष्कलंक हो जाएगा। विश्वास किया जाता है कि गंगा के दिव्य शरीर के स्पर्श मात्र से हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भारतीय देवकथा में सर्वाधिक रंगीन कहानियाँ हैं उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें गंगा स्वर्गलोक से उतरकर पृथ्वी पर आई थीं।

एक समय कुछ राक्षस थे जो ब्राह्मण ऋषि-मुनियों को तंग करते थे और उनके भजन-पूजा में बाधा डाला करते थे। जब उनका पीछा किया जाता था तो वे समुद्र में छिप जाते थे, मगर रात में फिर आकर सताया करते थे। एक बार ऋषियों ने ऋषि अगस्त्य से प्रार्थना की कि वे उनको राक्षसी प्रलोभन की यातना से मुक्त करें। उनकी सहायता के उद्देश्य से अगस्त्य ऋषि राक्षसों समेत समुद्र को पी गए। इस प्रकार उन राक्षसों का अंत हो गया किंतु पृथ्वी जल से शून्य हो गई। तब मनुष्यों ने एक और ऋषि भगीरथ से प्रार्थना की कि वे सूखे की विपदा से उन्हें छुटकारा दिलाएँ। इतना बड़ा वरदान पाने के योग्य बनने के लिए भगीरथ ने तपस्या करने में एक हजार वर्ष बिता दिए और फिर ब्रह्मा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे स्वर्गलोक की नदी गंगा को- जो आकाश की नक्षत्र धाराओं में से एक थी- पृथ्वी पर उतार दें। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने यथाशक्ति प्रयत्न करने का वचन दिया और कहा कि वे इस मामले में शिव से सहायता माँगेंगे। उन्होंने समझाया कि अगर स्वर्गलोक की वह महान नदी अपने पूरे वेग और समस्त जल के भार के साथ पृथ्वी पर गिरी तो भूकंप आ जाएँगे और उसके फलस्वरूप बहुत विध्वंस होगा। अतः किसी को उसके गिरने का आघात सहकर उसका धक्का कम करना होगा और यह काम शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। भगीरथ उपवास और प्रार्थनाएँ करते रहे। समय आने पर शिव पसीजे। उन्होंने गंगा को अपनी धारा पृथ्वी पर गिराने दी और उसके आघात को कम करने के लिए उन्होंने पृथ्वी और आकाश के बीच अपना सिर रख दिया। स्वर्गलोक का जल तब उनके केशों से होकर हिमालय में बड़े सुचारु रूप से बहने लगा और वहाँ से भारतीय मैदानों में पहुँचा जहाँ वह समृद्धि, स्वर्गलोक के आशीर्वाद और पापों से मुक्ति लेकर आया।

कुछ आसान और अचूक टोटके

समय की कमी और भागदोड़ से भरी जिंदगी ने आज इंसान को हेरान परेशान कर रखा है। यहां हम जिन टोटकों यानि कि युक्तियों को दे रहें हैं वे ऐसी ही अद्भुत और कारगर युक्तियां हैं। ये तुलसी रामायण के प्रामाणिक और शक्ति सम्पन्न अंस हैं। जिनको सूर्योदय से पूर्व पूर्ण शांत एवं पूर्ण एकांत स्थान पर मात्र 15 मिनिट मंत्र की तरह जपने से इच्छित मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।

- धन-समृद्धि की वृद्धि के लिये - जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं, सुख सम्पति नाना विधि पावहिं ।
- मुकद्दमा जीतने के लिये - पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना ।
- पुत्र प्राप्ति के लिये - प्रेम मगन कोशल्या निशिदिनि जात न जान, पुत्र सनेह बस माता बालचरित कर गान ।

कौन थीं कृष्ण की 16108 रानियां?

श्रीकृष्ण का नाम आते ही हमारे मन असीम प्रेम उमड़ता है। सभी जानते हैं कि असंख्य गोपियां थी जो श्रीकृष्ण से अनन्य प्रेम करती थीं। परंतु उनकी शादी श्रीकृष्ण से नहीं हो सकी। श्रीकृष्ण की प्रमुख पटरानी रुकमणी पटरानी रुकमणी सहित उनकी 8 पटरानियां एवं 16100 रानियां थीं। कुछ विद्वानों का यह मत है कि कृष्ण की प्रमुख रानियां तो आठ ही थीं, शेष 16,100 रानियां प्रतीकात्मक थीं। इन्हें वेदों की ऋचाएं माना गया है। ऐसा माना जाता है चारों वेदों में कुल एक लाख श्लोक हैं। इनमें से 80 हजार श्लोक यज्ञ के हैं, चार हजार श्लोक पराशक्तियों के हैं। शेष 16 हजार श्लोक ही गृहस्थों या आम लोगों के उपयोग के अर्थात भक्ति के हैं। इन श्लोकों को ऋचाएं कहा गया है, ये ऋचाएं ही भगवान कृष्ण की पत्नियां थीं। श्रीकृष्ण की प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र एवं प्रत्येक रानी से 1-1 पुत्री का जन्म हुआ।

क्या है कृष्ण की रासलीला का सच ?

कुछ लोग अपने आपको कृष्ण भक्त या कृष्ण के अनुयाई बताकर चेहरे पर बड़े गर्व के भाव व्यक्त करते हुए घूमते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि क्या है कृष्ण का मतलब? क्या था कृष्ण का व्यक्तित्व, और क्या क हते हैं कृष्ण अपनी गीता में क्या रसिया कृष्ण की गीता में रासलीला का बड़ा ही सुन्दर वर्णन आया है इतना पूछने पर, अपने आप को कृष्ण का अनुयाई कहने वाले ये तथाकथित कृष्ण भक्त खिसियाकर बगलें झांकने लगते हैं।

वास्तविकता यह है कि रास शब्द रस से ही बना है। जबकि रस शब्द का अर्थ है आनंद। आगे चलकर हम देखते हैं कि संगीत के साथ किये जाने वाले नृत्य को ही काव्य अथवा साहित्य में रास संज्ञा से सूचित किया जाने लगा। पता नहीं रासलीला को लेकर समाज में यह गलत मान्यता कैसे प्रचलित हो गई। संस्कृत कवि जयदेव ने अपने काव्य में कृष्ण को नायक बनाकर कई श्रृंगारिक गीतों की रचना की जो कि पूरी तरह काल्पनिक एवं मनगढ़ंत हैं। जयदेव की परंपरा को ही बाद में विद्यापति....से लेकर सूरदास ने आगे बढ़ाया।

नौ वर्ष के कृष्ण- एक अति महत्वपूर्ण बात और भी है जिससे बहुत कम ही लोग परिचित हैं। वह यह है कि जब कृष्ण ने हमेशा-हमेशा के लिये गोकुल-वृंदावन छोड़ा तब उनकी उम्र मात्र नौ वर्ष की थी। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि कृष्ण जब गोप-गोपिकाओं के साथ गौकुल-वृंदावन में थे तब नौ वर्ष से भी छोटे रहे होगें। अति मनोहर रूप, बांसुरी बजाने में अत्यंत निपुण, अवतारी आत्मा होने के कारण जन्मजात प्रतिभाशाली आदि तमाम बातों के कारण वे आसपास के पूरे क्षेत्र में अत्यंत् लोकप्रिय थे। नौ वर्ष के बालक का गोपियों के साथ नृत्य करना एक विशुद्ध प्रेम और आनंद का ही विषय हो सकता है। अत कृष्ण रास को शारीरिक धरातल पर लाकर उसमें मोजमस्ती या भोग विलास जेसा कुछ ढूंढना इंसान की स्यवं की फितरत पर निर्भर करता है। कृष्ण के प्रति कोई राय बनाने से पूर्व इंसान को गीता को समझना होगा क्योंकि उसके बिना कोई कृष्ण को वास्तविक रूप में समझ ही नहीं पाएगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जबकि अब केवल एक पद रिक्त रह गया है। नियुक्त किए गए नए न्यायाधीशों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमणि मोहना शामिल हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन सभी की नियुक्ति औपचारिक रूप से प्रभावी हो गई है। यह नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश, 2026 के बाद हुई हैं। इस अध्यादेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है।

सपा सांसद का दिल पाक के लिए धड़कता है : कृष्णम

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल में मदरसों के अंदर भी वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे लेकर यूपी तक सियासत गर्मा गई है। सपा सांसद ने जियाउर्रहमान बर्क ने इस फैसले का विरोध किया, जिसपर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सपा सांसद का दिल हमेशा ही पाकिस्तान के लिए धड़कता है, इसलिए वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। दरअसल विवाद पश्चिमी बंगाल के मदरसों वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य बनाने के बाद शुरू हुआ। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी मदरसों को निर्देश दिया है कि अब से सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। यूपी में भी सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में वंदे मातरम पर जोर दिया है।इस लेकर जब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देश भक्ति जबरदस्ती बुलवाने से नहीं होती। राष्ट्रगान का सभी लोग सम्मान करते हैं।

अन्नामलाई पार्टी छोड़ बना सकते हैं नया दल!

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई में बड़े उथल-पुथल नजर आ रहे हैं। अटकलें हैं कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई बीजेपी छोड़ सकते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि वह नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि, इन अटकलों को लेकर अन्नामलाई ने आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये चर्चाएं ऐसे समय पर हो रही हैं, जब कहा जा रहा है कि अन्नामलाई को बीजेपी में बड़ी भूमिका दी जा सकती है।मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अन्नामलाई बीजेपी छोड़ने और नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल, इसके संकेत उनके समर्थकों की सक्रियता से भी मिल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर पार्टी के नामों और झंडे की डिजाइन्स को लेकर पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि, खुद अन्नामलाई ने इसे लेकर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाल ही में अन्नामलाई ने तीन भाषा मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से अलग रुख अपनाया था।

ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में एसआईआर शुरु

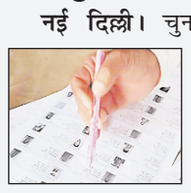

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव आयोग ने 14 मई को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का आदेश दिया था। उसी प्रक्रिया के तहत अब ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से एन्यूमरेशन फेज शुरू हो गया है। एसआईआर के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन करेंगे और फॉर्म जमा कराएंगे। आयोग ने कहा है कि 28 जून 2026 तक जिन लोगों के फॉर्म चुनाव पंजीकरण अधिकारी को मिल जाएंगे, उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। आयोग ने कहा है कि एसआईआर अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

दिलीप घोष ने सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले को बताया नाटक

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर किसी ने हमला नहीं किया। उन्होंने बनर्जी के आरोपों को नाटक करार देते हुए लोगों को सलाह दी कि वे उनकी बातों को गंभीरता से न लें। उन्होंने टीएमसी सांसद को सतर्क रहने और सदन से बाहर न निकलने की सलाह भी दी, क्योंकि घोष ने कहा कि कल्याण बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सबने देखा कि किसी ने उन्हें (कल्याण बनर्जी को) धक्का नहीं दिया और न ही उन पर हमला किया। हमने सदन में भी उनका नाटक देखा है और यहां भी हम इसे हर जगह देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने आगे कहा कि वे एक वरिष्ठ नेता और वकील रहे हैं, और उनके व्यवहार को लेकर हमेशा शिकायतें रही हैं। उनके खिलाफ जनता में काफी आक्रोश है। उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह का नाटक उन्हें शोभा नहीं देता।

सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी में महा-विद्रोह

ममता बनर्जी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए दो विधायकों को निकाला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर सुलग रही असंतोष की आग अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी आलाकमान ने कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को अपने दो मौजूदा विधायकों— संदीपान साहा और ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई ने उन अटकलों पर मुहर लगा दी है कि चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी नेताओं और विधायकों का एक बड़ा धड़ा ममता बनर्जी के नेतृत्व से नाराज चल रहा है और तृणमूल के भीतर एक बड़ा बिखराव शुरू हो चुका है।

टीएमसी द्वारा जारी एक आधिकारिक और सख्त बयान के अनुसार, इन दोनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की तात्कालिक वजह पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर रविवार को बुलाई गई एक महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक रही। 2026 के चुनावी नतीजों के बाद पार्टी के भविष्य और रणनीति को लेकर बुलाई गई इस समीक्षा बैठक से संदीपान साहा और ऋतब्रत बनर्जी, दोनों ही नदारद रहे। इसके अलावा, पार्टी ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि यह लगातार देखा जा रहा था कि दोनों विधायक सार्वजनिक मंचों और निजी चर्चाओं में ऐसे बयान दे रहे थे जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हितों के लिए बेहद हानिकारक और नुकसानदेह थे।

टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व ने इस अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त न करने का संदेश देते हुए दोनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी द्वारा जारी निष्कासन पत्र में कहा गया : इस पूरे मामले पर गंभीर और उचित विचार-विमर्श करने के बाद, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सक्षम प्राधिकारी ने आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, इस नोटिस के जारी होने की तारीख से आप पार्टी से जुड़े किसी भी पद, जिम्मेदारी, दर्जे या विशेषाधिकार को धारण करने के हकदार नहीं रहेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में हुए ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन और सुवेंदु अधिकारी के

नेतृत्व में बीजेपी की नई सरकार के गठन के बाद से ही तृणमूल के खेमे में भारी बेचैनी है। दस साल से अधिक समय तक सत्ता का सुख भोगने वाली पार्टी के विधायक अब विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं हैं।

अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि संदीपान साहा और ऋतब्रत बनर्जी का निष्कासन तो सिर्फ एक शुरुआत है; अंदर ही अंदर कई अन्य विधायक और वरिष्ठ नेता भी पाला बदलने या अपना नया रास्ता चुनने की तैयारी में हैं। ममता बनर्जी ने इन दोनों विधायकों पर गाज गिराकर बाकी असंतुष्टों को एक सख्त चेतावनी देने की कोशिश की है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या यह कार्रवाई टीएमसी में मचने वाले संभावित महा-विद्रोह को रोक पाती है या नहीं।

अभिषेक बनर्जी पर हमला : टीएमसी करेगी लोकसभा स्पीकर को सूचित

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को देंगे और इस मामले में अदालत भी जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। शनिवार को सोनारपुर में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने के दौरान अभिषेक बनर्जी पर ईंटों, पत्थरों और अंडों से हमला किया गया। टीएमसी नेता की आंख में चोट आई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि यह हमला भाजपा प्रायोजित था और उनकी जान लेने की कोशिश थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की।

सीबीएसई मार्किंग विवाद: सिस्टम में सेंध का आरोप

जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई

नईदिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 1 जून को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने स्वीकार किया है कि उसकी ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली में सुरक्षा खामी आई है। सीबीएसई ने घोषणा की कि वह ऑनमार्क पोर्टल में खामियों की निगरानी कर रहा है और सिस्टम को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। एक्स पर एक पोस्ट में, रमेश ने अगस्त 2025 में जारी किए गए प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) में अनियमितताओं को उजागर किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस मामले को संभालने के तरीके पर सवाल उठाते हुए उन्हें अहंकार और अक्षमता का प्रतीक बताया। उन्होंने सरकार पर ऑनमार्क पोर्टल को सहायता प्रदान करने वाली कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

रमेश ने लिखा कि अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम में साइबर सुरक्षा खामियों को हफ्तों तक नकारने के बाद, सीबीएसई ने आखिरकार स्वीकार किया है कि सिस्टम में सेंध लग गई है। लेकिन वह अपने ठेकेदार COEMPT के खिलाफ क्या कार्रवाई करने की योजना बना रहा है? कुछ खास नहीं। ऐसा लगता है कि सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय में COEMPT के संरक्षकों को पहले से ही पता था कि COEMPT इस काम के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

उन्होंने आगे कहा कि अगस्त 2025 के अपने आरएफपी में, सीबीएसई ने उन विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट करने का

अधिकार अपने पास रखा था जो प्रभावी ढंग से काम करने में असमर्थ थे। सितंबर में, सीबीएसई ने एक शुद्धिपत्र जारी किया, जिससे इन विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट करने का उसका अपना अधिकार वापस ले लिया गया। यह COEMPT को बचाने का एक समझ से परे, सरकार समर्थित प्रयास है, और यह COEMPT को आधिकारिक तौर पर अनुबंध मिलने से पहले ही शुरू हो गया था।

रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कांग्रेस पार्टी की मांग को दोहराते हुए कहा कि देश को कब तक मंत्री प्रधान को झेलना पड़ेगा, जिनके मंत्रालय ने निविदाओं में ऐसी अकल्पनीय अनियमितताओं को अंजाम दिया है, जिनकी वजह से लाखों छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है? मंत्री प्रधान अहंकार और अक्षमता की साक्षात मूर्ति हैं, जो राष्ट्र के प्रति किसी भी जिम्मेदारी से ऊपर अपने राजनीतिक एजेंडे को रखते हैं। प्रधानमंत्री को न तो स्वयं और न ही अपने सहयोगियों को ईमानदारी या नैतिकता के किसी मानक पर खरा उतरते देखा गया है। लेकिन मंत्री प्रधान को अपने राजधर्म का पालन करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।

कांग्रेस चिंतन शिविर के समापन में पहुंचे राहुल

जिलाध्यक्षों के परिवार से मिले

जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अजमेर जिले के पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन एवं संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। वाइल्ड रोज रिसॉर्ट में आयोजित इस शिविर में देशभर से आए कांग्रेस पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर दिया।

शिविर में राजस्थान के 50 और दिल्ली के 15 जिला अध्यक्षों सहित प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने प्रशिक्षण शिविर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने जिला अध्यक्षों को संगठन विस्तार, जनसंपर्क और पार्टी की विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया।

इस दौरान शिविर में शामिल जिला अध्यक्षों के परिवारजन भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। राहुल गांधी ने परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।

इससे पहले राहुल गांधी सुबह 10:05 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने राहुल गांधी को पारंपरिक हल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से पुष्कर के लिए रवाना हुए।

गौरतलब है कि चिंतन शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश उनका दौरा अंतिम समय में रद्द हो गया। शिविर के समापन के साथ संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

खेल
प्रमुख समाचार

क्या वैभव सूर्यवंशी को जल्द मिलेगी टीम इंडिया में जगह?

अहमदाबाद। आईपीएल 2026 में अपने धमाकेदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत को हैरान करने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का खेल दिखाया, उसके बाद टीम इंडिया में उनके भविष्य को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा 776 रन बनाए। उन्होंने 237.30 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए पूरे सीजन में गेंदबाजों की जमकर खबर ली।

आईपीएल 2026 के समापन के बाद बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने वैभव की जमकर तारीफ की और उनके भविष्य को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। सैकिया ने कहा, यह शानदार सीजन रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रशंसकों ने इस आईपीएल का भरपूर आनंद लिया होगा। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए आरसीबी को बधाई। वैभव सूर्यवंशी एक बेहतरीन उभरते हुए खिलाड़ी हैं और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। बीसीसीआई उन्हें क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उनके इस बयान को वैभव के लिए बड़े भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास में नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वह महज 15 साल और 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड साई सुदर्शन के नाम था, जिन्होंने 2025 में 23 साल 231 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीती थी। वहीं 2023 में शुभमन गिल ने भी युवा उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। आगामी महिला टी20 विश्व कप को लेकर भी बीसीसीआई सचिव ने भरोसा जताया। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में यही सबसे बड़ी चुनौती है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 543 अंक लुढ़का निफ्टी 23,383 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के सेशन में दबाव में रहा और प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। स्वास्थ्य और क्क- बैंक शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली, जबकि निवेशक अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर चल रही चर्चाओं का आकलन करते रहे। निफ्टी 50 में 165.15 अंक यानी 0.70 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई और यह 23,382.60 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 508.40 अंक यानी 0.68 प्रतिशत टूटकर 74,267.34 के स्तर पर आ गया। निफ्टी 50 के प्रमुख लूजरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, श्रेयम फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शामिल रहे। इन शेयरों में बिकवाली का दबाव बाजार की कमजोरी का प्रमुख कारण बना। ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.45 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ।

एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की बढ़ोतरी

नईदिल्ली। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल रिफाइनिंग और ईंधन मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। कंपनी ने इसकी कीमत में 42 रुपये की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 जून से लागू हो गई हैं। नई कीमतों के अनुसार, दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3,071.50 रुपये से बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गई है। वहीं, कोलकाता में इसकी कीमत 53.50 रुपये बढ़कर 3,255.50 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम आमतौर पर ईंधन और गैस की खुदरा कीमतों में एक साथ बदलाव करते हैं। मीडिया के अनुसार, 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

एक महीने में यूपीआई से 23 अरब लेनदेन

नई दिल्ली। क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट हो गया- यह वाक्य अब हर भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। चाय की टपरी से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल्स और हवाई सफर तक, हर जगह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का दबदबा साफ नजर आता है। भारत के इस स्वदेशी डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने अब एक नया और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, यूपीआई ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए मई 2026 में नया इतिहास रच दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक, मई महीने में यूपीआई के जरिए होने वाले लेनदेन ने वॉल्यूम (कुल संख्या) और वैल्यू (कुल रकम) दोनों ही पैमानों पर एक नया शिखर छू लिया है।

जीएसटी क्लेकशन मई में 1.94 लाख करोड़ रु. के पार

नईदिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मई में 3.2 प्रतिशत बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। यह वृद्धि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में सुधार तथा आयात से मिलने वाले कर संग्रह में लगातार बढ़ोतरी के कारण हुई। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। मई 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपए था। घरेलू लेनदेन से मई के दौरान केंद्रीय जीएसटी संग्रह 37,397 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 45,143 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि में कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो घरेलू मांग को दर्शाती है। वहीं सेवाओं के क्षेत्र में यह वृद्धि 22.2% रही जो घरेलू खपत की मजबूती को दिखाती है।

कमजोर मानसून तो महंगाई का लगेगा तड़का, अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

मौसम विभाग द्वारा 29 मई को जून से सितंबर मानसून के दौरान 10 प्रतिशत कम बरसात का पूर्वानुमान बेहद चिंताजनक का कारण बन गया है। इससे पहले जारी पूर्वानुमान में 8 प्रतिशत कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई थी। लगभग दस साल बाद देश में कमजोर मानसून के हालात रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिए यह इसलिए और भी अधिक चिंतनीय हो जाता है कि एक और अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसके कारण भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश कच्चे तेल और गैस की समस्या से दो चार हो रहे हैं और इसका सीधा असर महंगाई बढ़ना हो रहा है। दूसरी और अब अलनीनों के प्रभाव से इस साल कमजोर मानसून के कारण 10 प्रतिशत कम बरसात होने से हालात और भी गंभीर होने की संभावना बनती जा रही है। करीब दस साल बाद ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर पूर्व को छोड़कर समूचे देश में कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता है कि पिछले सालों में भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगभग सटीक रहने लगे हैं। मजे की बात यह है कि इस साल गर्मी भी भीषण पड़ रही है और पिछले एक माह में ही जलाशयों में उपलब्ध पानी में तेजी से कमी आई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश के प्रमुख 166 जलाशयों में कुल भराव क्षमता का 24 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है और तेजी से पानी कम होता जा रहा है। दक्षिण भारत के हालात अधिक गंभीर है और वहां लगभग 17 प्रतिशत ही पानी रह गया है। उत्तरी भारत के जलाशयों में 26 तो पश्चिमी भारत के जलाशयों में 28 प्रतिशत के

आसपास ही पानी रह गया है। मानसून भी तय समय से बिलंबित हो रहा है।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसूनी बरसात पर बहुत कुछ निर्भर करती है। देश में मानसून सीजन में 87 सेमी बरसात होती है। पूर्वानुमानों को माने तो 2018 में 91 प्रतिशत बरसात हुई थी उसके बाद के सालों में मानसून लगभग अच्छा ही रहा है। पिछले सालों में मानसून की स्थिति देखें तो 2023 में मानसून अवश्य कमजोर रहा है अन्यथा देश में मानसूनी वर्षा 100 प्रतिशत के आसापास व इससे अधिक ही रही है। कमजोर मानसून के कारण भूजल स्तर में गिरावट, अधिक पानी पर निर्भर धान, तिलहन और दलहन की फसल प्रभावित होगी और इस कारण से खाद्य महंगाई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इससे आम आदमी की थाली पर असर पड़ेगा और सब्जी, दाल और अनाज सभी के भाव बढ़ने का असर दिखाई देगा। इसी तरह से देश के अनेक हिस्सों में पीने के पानी की दिक्कत आम है। बांधों में तेजी से पानी की कमी और मानसून कमजोर रहने से पानी की कम आवक रहती है तो निश्चित रुप से सिंचाई व पेयजल दोनों के लिए पानी की दिक्कत होगी। जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर असर होगा तो कुल मिलाकर अर्थ व्यवस्था को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता।

दरअसल देश में एक समय था जब सूखा आम होता था और व्यापक स्तर पर अकाल राहत कार्य संचालित होते थे। हांलाकि देश के हालातों में काफी सुधार हुआ है और अकाल को तो लगभग भूल ही चुके हैं। पर सवाल वहीं का वहीं है कि जल संचयन के जो प्रयास होने चाहिए थे और उनका जिस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए था वह अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार के सामने कमजोर मानसून के हालात से निपटने की बड़ी चुनौती आने वाली है। सबसे अधिक तो जल संग्रहण की चुनौती होगी क्योंकि प्राकृतिक जल संग्रहण के रास्ते शहरीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन सोच के साथ ठोस प्रयास नहीं होने से बरसात के पानी का सही तरीके से संग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। जितने पानी की साल भर आवश्यकता होती है उससे अधिक बरसाती पानी तो बह जाता है। इसके अलावा पानी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बढ़ गए हैं। कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की किस्में विकसित करने में हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पायें हैं।

मुख्यमंत्री जन चौपाल में ग्रामीणों किया सीधा संवाद

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के अंतर्गत नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड स्थित अबूझमाड़ अंचल की ग्राम पंचायत गारपा में आयोजित जन चौपाल में पहुँचकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया। जन चौपाल में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच सीधे संवाद का सशक्त माध्यम है। इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुँचाना तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा, जिसके कारण यहां विकास कार्य वर्षों तक बाधित रहे। लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और अबूझमाड़ सहित पूरे बस्तर क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर और आदिवासी अंचलों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अनेक बार बस्तर का दौरा कर क्षेत्र के विकास एवं शांति स्थापना के प्रयासों की लगातार समीक्षा कर चुके हैं। राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में भी सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं तेजी से पहुंचें। गारपा सहित आसपास के क्षेत्रों में सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण के कार्य तेजी से संचालित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन सुगम होगा और विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तथा सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण किए जाएंगे।जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं से चर्चा की। महिलाओं ने बताया कि योजना से प्राप्त राशि का उपयोग वे घरेलू जरूरतों की पूर्ति के साथ-साथ अपनी बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खातों में जमा कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कृषि एवं आजीविका संबंधी विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा तथा पशुपालन और बकरी पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही वनोपज संग्राहकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।उन्होंने ग्रामीणों को रामलला दर्शन योजना, अटल डिजिटल सेवा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री बस सेवा, मनरेगा जॉब कार्ड, लखपति दीदी योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की तथा आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

पत्थर शरीर वाली बच्ची के उपचार को लेकर बाल आयोग सक्रिय

■ **डॉ. वर्णिका शर्मा के निर्देश पर बच्ची के बेहतर उपचार की दिशा में बड़ा कदम**

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा द्वारा सोशल मीडिया में प्रसारित समाचार एवं आयोग को प्राप्त आवेदन पत्र का संज्ञान लेते हुए बीजापुर जिले के नेलसनार क्षेत्र अंतर्गत बेंगोफर पारा, कौरगांव निवासी गंभीर रूप से बीमार नाबालिग बच्ची के उपचार हेतु प्राप्त दान एवं सहायता राशि के संबंध में जांच की कार्यवाही कराई जा रही है।

प्राप्त आवेदन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ब्रजराज रजक एवं दीपक ध्रुवे द्वारा बच्ची के उपचार के लिए सार्वजनिक सहयोग राशि एकत्रित किए जाने तथा भुगतान संबंधी विवरणों पर प्रश्न उठाए गए थे, जिस पर डॉ. वर्णिका शर्मा द्वारा संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दीपक ध्रुवे द्वारा जांच प्रारंभ होने से पूर्व बच्ची के परिवार को 39,000 की राशि प्रदान की गई थी तथा जांच के दौरान अतिरिक्त 22,400 की राशि बच्ची की माता एवं उसके भाई की उपस्थिति में तथा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त 5,000 की राशि संबंधित बैंक खाता होल्ड होने के कारण बच्ची के चाचा के खाते में जमा कराई गई थी, जिसे बाद में उनके चाचा द्वारा बच्ची की माता को प्रदान किया गया।

जांच में यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ब्रजराज रजक द्वारा बच्ची के उपचार हेतु वीडियो प्रसारित कर स्वयं का क्यूआर कोड साझा किया गया था। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि ब्रजराज रजक द्वारा जांच से पूर्व भी कुछ राशि बच्ची के उपचार हेतु परिवार को प्रदान की जा चुकी थी। वहीं पूछताछ के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि 18,000 की शेष राशि उनके पास उपलब्ध थी, जिसे जांच उपरांत बच्ची के परिवार को प्रदान कर दिया गया। डॉ. वर्णिका शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रकरण से संबंधित सभी वित्तीय लेन-देन, प्राप्त दान राशि, बैंक खातों एवं भुगतान विवरणों की तथ्यात्मक एवं कंडिकावार जांच सुनिश्चित करते हुए संपूर्ण प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा दोष पाया जाता है।

नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए बढ़ रही जनभागीदारी

रायपुर । अंतरराष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नशा मुक्ति एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को तंबाकू, धूम्रपान और नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इन कार्यक्रमों में युवाओं, महिलाओं, पुनर्वास लाभार्थियों तथा आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिचर्चा सह बैठक आयोजित कर धूम्रपान एवं नशापान के विरुद्ध व्यापक जनजागृति का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बरमकेला के अधिकारी-कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, स्वास्थ्य सुपरवाइजर तथा मितानिनों ने सहभागिता निभाई। इस अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्था की दीदियों ने मानसिक स्वास्थ्य, मेडिटेशन तथा तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर विस्तृत जानकारी देते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नवजीवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सारंगढ़ में पुनर्वास प्राप्त कर रहे हितग्राहियों एवं स्टाफ के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र के अधीक्षक श्री रोशन जायसवाल ने युवाओं से सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए बताया कि जागरूकता और सकारात्मक वातावरण से नशे की लत पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई ।वहीं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उप मुख्यमंत्री साव ने आम पेड़ के नीचे लगाई चौपाल

रायपुर। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक श्री अरुण साव ने आज लोरमी के ग्राम जरहापारा में आम पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने इस दौरान गांव में हुए विकास कार्यों पर चर्चा कर जनकल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने जरहापारा में देवगुड़ी निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान किया। उन्होंने ग्रामीणों के आवेदनों के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि डबल इंजन की सरकार वनांचलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जनमन योजना एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से वन ग्रामों को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।

उद्योग मंत्री देवांगन ने किया विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमिपूजन

रायपुर। नगर पालिक निगम कोरबा के कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत वार्ड क्र. 35 एवं 36 को 02 करोड़ 95 लाख रूपये के लागत वाले 07 नये विकास कार्यो की सौगात प्राप्त हुई है, प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर मती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता में खरमोरा में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान इन सभी विकास कार्यो का भूमिपूजन उनके हाथों किया गया। इस अवसर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर एवं पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधिगण विशिष्ट रूप से उपस्थित थे।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 01 करोड़ 94 लाख 70 हजार रूपये की लागत से वार्ड क्र. 36 अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग कालोनी में नाली निर्माण तथा जिला चिकित्सालय मुख्य मार्ग तक नाला का निर्माण जिला खनिज न्यास मद से किया जाना हैं। इसी प्रकार मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद से 20 लाख रूपये की लागत से वार्ड क्र. 36 साधराम राठौर घर से राठिया समाज भवन तक सी.सी.रोड एवं नाली का निर्माण कार्य, इसी मद से 20 लाख रूपये की लागत से वार्ड क्र. 36 स्थित निर्मला स्कूल से विनोद सोनवानी घर तक नाली का निर्माण एवं इसी मद से 05 लाख रूपये की लागत से वार्ड क्र. 36 डिंगापुर जंगल खटाल में मंच निर्माण का कार्य कराया जाना हैं। इसी प्रकार जिला खनिज संस्थान मद से 35 लाख 80 हजार रूपये की लागत से वार्ड क्र. 35 अंतर्गत गोकुलनगर गोठान हेतु बाउण्ड्रीवाल शेड, अतिरिक्त कक्ष व शौचालय का निर्माण कार्य , इसी मद से 15 लाख रूपये की लागत से वार्ड क्र. 35 न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी खरमोरा गेट से मेन रोड तक सी.सी. रोड का निर्माण तथा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद से 05 लाख रूपये की लागत से वार्ड क्र. 35 मेन रोड खरमोरा हनुमान मंदिर से कमल राठौर के घर तक सी.सी. रोड का निर्माण भी निगम द्वारा किया जाना हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

राज्य में प्रशासनिक अराजकता हावी: दीपक बैज

रायपुर। बेमेतरा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में फैली अव्यवस्था राज्य की बेलगाम नौकर शाही का एक नमूना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। बेमेतरा में पूरी सरकार के समक्ष सरकारी कार्यक्रम में अव्यवस्था पसरी रहती है पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को मंच से रोष प्रकट करना पड़ता है। इसके पहले विधायक के सामने जनपद का सीईओ, कार्यकर्ता को बिगाड़ लेने की चुनौती देता है। बेमेतरा के ही सुशासन त्यौहार में वरिष्ठ मंत्री, सरकारी अमले और पुलिस पर शराब बेचने का आरोप लगाते है। राजधानी में भरे मंच से वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के कोने-कोने में अधिकारियों को अवैध शराब बिकवाने का खुला आरोप लगाते है। यह घटनाएं बताती है कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री दयालदास बघेल के द्वारा अधिकारियों को दी गयी चेतावनी बताती है कि सत्तारुढ़ दल के वरिष्ठ नेता भी सरकार और सरकारी अमले के काम-काज से संतुष्ट नहीं है।

कोल उत्खनन पर साय सरकार अपना मत स्पष्ट करें : शुक्ला

रायपुर। साय सरकार हसदेव अरण्य जंगल के बारे में अपना मत स्पष्ट करें। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि साय सरकार हसदेव में जंगल कटाई होने देगी या केंद्र की अनुमति के खिलाफ राज्य के पर्यावरण के हित में विरोध करेगी। हालांकि अभी तक ढाई साल में भाजपा सरकार ने अडानी के हितो के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसा लगता है राज्य की भाजपा सरकार अडानी के लिये चल पड़ी है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मुनाफे के लिए सरगुजा रेंज के केते एक्सटेंशन के खुदाई का गौतम अडानी को देने के लिए केन्द्र सरकार ने अनुमति दी है। अब रामगढ़ की पहाड़ियां, प्राचीन नाट्यशाला, सीता गुफा, जानकी रसोई, प्रभु श्री राम के वन गमन पथ की पुण्य स्मृतियों को अडानी के आर्थिक लाभ के लिए संकट में डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइनिंग और पिट हेड कोल वॉशरी परियोजना के लिए 1742.60 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन उपयोग में बदलने की सिफारिश कर दी है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास भेजा गया है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही 5 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई का रास्ता साफ हो जाएगा।

जनगणना के आंकड़े बदलने दबाव डाला जा रहा: ठाकुर

रायपुर। जनगणना कार्य मे लगे शिक्षकों पर वास्तविक जानकारी बदलने का दबाव डालने का आरोप लगाते हुई प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा केंद्र की भाजपा सरकार ने पहले हर 11 साल में होने वाली जनगणना को समय पर होने नही दिया।अब जनगणना हो रही है तो जनता द्वारा दी जा रही वास्तविक जानकारी को बदलने जनगणना कार्य मे लगे शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों पर अनैतिक दबाव डाल रही है। ऐसे शिकायत लगातार मिल रही है।12 साल में केंद्र सरकार ढेर सारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने एवं उससे जनता को लाभ होने का दावा कर रही थी लेकिन सच्चाई जनगणना से सामने आ रही है। जनता द्वारा दी गई जानकारी में घरों में नल नही होना, पीएम आवास नही मिलना, शौचालय नही होना,पात्र होने के बावजूद गरीबी रेखा सर्व सूची में नाम नही होना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन योजना,मुद्रा योजना का लाभ नही मिलना,आयुष्मान योजना कार्ड नही बनाना, राशन कार्ड नही होना,मनरेगा से काम नही मिलना, मुद्रा योजना से वंचित होना, सहित अन्य जानकारी दी जा रही है जिसे केंद्र सरकार के दावे खोखले साबित हो रही है।

नियमितीकरण मामले में सरकार क्यों चुप है: वर्मा

रायपुर। दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि 100 दिन के भीतर नियमितीकरण का वादा था, ढाई साल बीत जाने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी ठगे जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में सुनवाई के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकारी संवैधानिक नियोक्ता है और गरीब कर्मचारियों के दम पर अपना बजट संतुलित नहीं कर सकती।उनके हित में सहानुभूति पूर्वक विचार कर चार महीने के भीतर निर्णय लेने के कठोर निर्देश जारी किया गया है। भाजपा सरकार की नीयत नहीं है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए और इसीलिए आउटसोर्सिंग के जरिए काम लेकर नियमित नियुक्तियों से बचने का कुत्सित प्रयास भाजपा की सरकार हर विभाग में कर रही है। भाजपा की सरकार ने कर्मचारियों के हर वर्ग को ठगा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू किया नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के हक का काटा गया पैसा लगभग 30 हजार करोड़ रूपया केंद्र की एजेंसी ने वापस नहीं लौटाया।

भाजपा सरकार ने महिलाओं को धोखा दिया : वंदना

रायपुर। भाजपा सरकार महिलाओं को धोखा दे रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को धोखा दिया, पहले रोजगार का वादा कर वोट लिया अब भूल गए। सरकार की बदनीयती के कारण प्रदेश की 3 लाख से अधिक महिलाएं जो स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार प्राप्त करती थी, बेरोजगार हो गयी है। भाजपा सरकार चुनाव में वादा करने के बाद उनको काम नहीं दे रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में वादा किया था पूरे प्रदेश में महिला समूहों को रेडी टू ईट का काम दिया जाएगा। सरकार में आने के बाद इसको भूल गए। जब विपक्ष और महिलाओं ने मांग किया तब एक साल पहले घोषणा किया कि पहले 6 जिलों में महिलाओं को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में काम देंगे, फिर सभी जिलों में देंगे। ढाई साल हो गया सिर्फ रायगढ़ जिले के कुछ प्रोजेक्ट में केवल 10 समूहों को एवं दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा ब्लॉक में काम दिया गया, पूरे जिले में नहीं। सभी 6 जिले की महिलाएं आज भी काम के इंतजार में है। जब 6 जिले में ढाई साल में काम नहीं दे पाए, तब पूरे प्रदेश में क्या देंगे? यह सरकार की बदनीयती है।

सुशासन तिहार 2026

समाधान शिविरों से ग्रामीणों को मिल रही त्वरित राहत

रायपुर। प्रदेशभर में संचालित सुशासन तिहार 2026 आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासकीय योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के विकासखंड ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत टमकी में आयोजित समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं रखीं तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त किया।धान खरीदी केंद्र के समीप आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करते हुए कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया, जिससे ग्रामीणों को तत्काल राहत मिली। शेष आवेदनों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों को समय-सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

शिविर में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। जरूरतमंद परिवारों को नवीन राशन कार्ड वितरित किए गए, वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाकर हितग्राहियों को उपलब्ध कराए गए, जिससे ग्रामीणों में उत्साह देखा गया।

सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित इस समाधान शिविर में ग्राम पंचायत टमकी सहित कुल 13 गांवों - खोड़, केशर, छतौलीबिजो, इंजानी, करवा, मसनकी, बेदमी, चिकनी, मयुरधक्की, लांजित, कुप्पा एवं खर्रा- के ग्रामीण शामिल हुए। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने शिविर को जनसमस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच बताया।प्रदेश में सुशासन तिहार के माध्यम से शासन और आमजन के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ-साथ योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।

5 जून को रायपुर में रोजगार मेला दिव्यांगजनों के लिए सुनहरा अवसर

रायपुर। विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा दिव्यांगजनों के लिए 5 जून 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. शशि अतुलकर, उपसंचालक रोजगार, विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर ने बताया कि यंग इंडिया के तत्वावधान में यह रोजगार मेला प्रात: 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार, रायपुर में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में अस्थिबाधित, बौने, कम सुनने वाले तथा देखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मेले में क्रेडालिस कैपिटल प्रा. लि., आई ट्रेड टेलीमेटिक्स निगरानी जीपीएस, रामा उद्योग प्रा. लि., बारबरिक ट्रांसफॉर्मर्स, अविनाश डेवलपर्स प्रा. लि., स्काई ऑटोमोबाइल एवं विश्वभारती ऑटोमोबाइल प्रा. लि. रायपुर सहित विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता एवं पद के अनुसार प्रतिमाह 11 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक वेतन प्रदान किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का कार्यक्षेत्र रायपुर एवं सिलतरा रहेगा उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के ऐसे इच्छुक दिव्यांगजन, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है तथा जो बिना व्हीलचेयर के चलने-फिरने में सक्षम हैं, रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं।

रोजगार मेले में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की मूल एवं छायाप्रति तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर उपस्थित होना होगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.